भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 629

2.12.2015 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री/विदेशी गणमान्यों का दौरा

629. श्री हरि मांझीः
मोहम्मद फैजलः
श्री गणेश सिंहः
श्री रामा किशोर सिंहः
श्री दुष्यंत चौटालाः
योगी आदित्यनाथः
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः
प्रो. के वी थॉमसः
श्री सी गोपालकृष्णनः
री एम उदयकुमारः
श्रीमती रक्षाताई खाडसेः
श्री एन के प्रेमचन्द्रनः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्रीमती कविता कलवकुंतलाः
श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डीः
श्री रत्न लाल कटारियाः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः
कुंवर हरिवंश सिंहः
श्री पी कुमारः
श्री सुल्तान अहमदः
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डीः
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधानः
श्री नारन भाई काछड़ियाः
श्री विद्युत वरण महतोः
श्री रामदास सी तडसः
श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः
प्रो. सौगत रायः
डॉ. मनोज राजोरियाः
श्री एस आर विजय कुमारः
श्री पी सी मोहनः

श्री टी जी वेंकटेश बाबूः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किए गए विदेशी यात्राओं का देश-वार ब्यौरा क्या है और कितने समझौते हुए हैं एवं सहयोग हेतु कितने क्षेत्रों, यदि कोई हो, की पहचान की गई, चर्चा हुई तथा इस पर कितना खर्च आया;

(ख) इस अवधि के दौरान भारत में यात्रा करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का देश-वार ब्यौरा क्या है तथा कितनी बैठकें हुईं, आगे के सहयोग के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया और कतने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए;

(ग) क्या प्रधानमंत्री के हाल के ब्रिटेन के दौरे के दौरान कोई परमाणु समझौता हुआ और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन दौरों के दौरान कतिपय देशों में चल विद्यमान आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई थी; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[जनरल (डॉ) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त)]

(क), (घ) तथा (ड.) सूचना संकलित कर ली गई है और अनुबंध 'क' तथा अनुबंध 'ख' पर दी गई है।

(ख) सूचना संकलित कर ली गई है और अनुबंध 'ग' पर दी गई है।

(ग) असैनिक परमाणु सहयोग विषयक संयुक्त घोषणा 2010 के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान 12-14 नवंबर 2015 के बीच असैनिक परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे दोनों देश परमाणु सुरक्षा सहित बिजली के उत्पादन के लिए पानी के विलवणीकरण, कृषि, स्वास्थ्य, परिचर्या, उद्योग और चिकित्सा आदि क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

*****

अनुलग्नक 'क'

प्रधानमंत्री की यात्राएं

पिछले एक वर्ष से अब तक के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा	किए गए व्यय	आयोजित वार्ताओं और आगे सहयोग के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा	समझौतों पर हस्ताक्षर किए	क्या आतंकवाद और कुछ देशों में प्रचलित मौजूदा स्थिति का मुद्दा चर्चा के लिए आया था - यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया है?
(क)				(घ) और (ड.)
भूटान का दौरा, 15-16 जून, 2014	भारत सरकार मिशनों विदेशों में डेबिट व्यय यात्रा के साथ शामिल प्रासंगिक एजेंसियों के लिए किए गए। यह जानकारी एकत्र की जा रही है।	पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा विदेशों में पहला दौरा। भूटान के साथ हमारे अद्वितीय और विशेष संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।	नेहरू-वांग्चुक छात्रवृत्ति का दोहरीकरण (1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए सालाना) 2. ई-पुस्तकालय की स्थापना	
ब्राजील का दौरा 15-16 जुलाई, 2014		प्रधानमंत्री ने 15-16 जुलाई 2014 को फ़ोर्टालेज़ा, ब्राजील में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वैश्विक शासन - राजनीतिक और आर्थिक दोनों, व्यापार, वित्त, क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों के रूप में वैश्विक मुद्दों सहित आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन, 2015 के बाद विकास के एजेंडे आदि के आवरण सुधार के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श और सर्वसम्मति के निष्कर्ष पर फ़ोर्टालेज़ा घोषणा पत्र जारी किए गए। 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित के लिए एक नए विकास बैंक की स्थापना तथा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) स्थापित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर,	6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित के लिए एक नए विकास बैंक की स्थापना तथा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) स्थापित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर, जो जो ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच एक बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप के रूप में कार्य करेंगे। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से ब्रिक्स देशों के निर्यात ऋण गारंटी एजेंसियों के बीच तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और शिखर सम्मेलन में पारस्परिक हित के नवाचार परियोजनाओं के वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए नवाचार पर एक अंतर-बैंक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।	ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कार्य सूची मदों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाक्रम और आतंकवाद को शामिल किया गया। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी घोर निन्दा की बात दोहराई और जोर दिया है यह किसी भी विचारधारात्मक, धार्मिक, राजनीतिक, जातीय, जातीय, या अन्य औचित्य पर आधारित रूप से आतंकवाद के किसी भी

		जो जो ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच एक बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप के रूप में कार्य करेंगे। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से ब्रिक्स देशों के निर्यात ऋण गारंटी एजेंसियों के बीच तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और शिखर सम्मेलन में पारस्परिक हित के नवाचार परियोजनाओं के वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए नवाचार पर एक अंतर-बैंक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।		कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
ब्राजील का दौरा 15-16 जुलाई, 2014		प्रधानमंत्री ने ब्रासीलिया में 16 जुलाई, 2014 को ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ के साथ एक द्विपक्षीय मुलाकात की थी।	'पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग', 'भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त करने और डेटा प्रोसेसिंग के लिए ब्राजील के एक भू-स्टेशन के विस्तार में सहयोग स्थापित व्यवस्था को लागू' पर तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों / समझौते और दौरे के दौरान 'गतिशीलता और कॉन्सुलर मुद्दों पर एक परामर्श तंत्र की स्थापना में सहयोग' पर हस्ताक्षर किए गए।	
नेपाल का दौरा, 3-4 अगस्त, 2014		यह 17 वर्षों के बाद नेपाल के लिए एक प्रधान मंत्री स्तर की द्विपक्षीय यात्रा थी। द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई।	1. पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के लिए विचारणीय विषय में पत्र के विनिमय। 2. घेंघा नियंत्रण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 3. दूरदर्शन और नेपाल टेलीविजन के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	
जापान का दौरा 30 अगस्त – 03 सितम्बर 2014		प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी ने भारत के निकट पड़ोस के अपने पहले गंतव्य के रूप में जापान को चुना है। भारत-जापान के बीच विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी के लिए संबंध को उन्नत बनाया गया था। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रियाओं और मंचों सहित क्षेत्रीय मंचों में भारत और जापान के बीच घनिष्ठ परामर्श और	1. भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और जापान के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग और आदान-प्रदान पर ज्ञापन। 2. स्वास्थ्य के क्षेत्र में जापान के भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन।	संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने अपराधियों, मूल और प्रेरणाओं की परवाह किए बगैर अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद

		समन्वय के दोनों नेताओं के महत्व को रेखांकित किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपराधियों, मूल और प्रेरणाओं की परवाह किए बगैर अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने में मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के लिए आतंकवाद के उभरते चरित्र के बारे में जानकारी और खुफिया सूचना की वृद्धि की साझेदारी के माध्यम से सहित इस पर बल दिया। उन्होंने आतंकवाद को बहुपक्षीय कार्रवाई और सक्रिय जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को अंतिम रूप देने और ग्रहण करने के माध्यम से शामिल करने का भी आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने साझा दृढ़ संकल्प की पुष्टि की, और 2014 के बाद अफगान नेतृत्व आर्थिक विकास, राजनीतिक बहुलवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता का आह्वान किया ताकि अफगानिस्तान में आतंकवाद, उग्रवाद और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त लोकतांत्रिक संयुक्त, स्वतंत्र, संप्रभु, स्थिर और राष्ट्र बनाने में मदद दी जा सके। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के लिए, विशेष रूप से इसे और अधिक प्रतिनिधि वैध, प्रभावी बनाने और 21वीं सदी की वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में इसके विस्तार के लिए तत्काल जरूरत की पुष्टि की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत को चार अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में एक पूर्ण सदस्य बनाने के लिए एक साथ काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह को मजबूत बनाने के उद्देश्य के साथ, अंतरराष्ट्रीय	3. भारत गणराज्य और जापान के विदेश मंत्रालय का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सहकारिता समझौता ज्ञापन। 4. सड़कों और सड़क परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और भूमि, मूलसंरचना, परिवहन मंत्रालय और जापान पर्यटन के बीच सहयोग की रूपरेखा। 5. वाराणसी के शहर (भारत गणराज्य) और क्योटो के शहर (जापान) के बीच साथी शहर संबद्धता के संबंध में आशय की पुष्टीकरण। 6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और जापान बैंक के बीच समझौता ज्ञापन।	का मुकाबला करने में मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के लिए आतंकवाद के उभरते चरित्र के बारे में जानकारी और खुफिया सूचना की वृद्धि की साझेदारी के माध्यम से सहित इस पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न देशों में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति पर चिंता की, और पुष्टि की कि इस विषय में आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने और बुनियादी ढांचा के उन्मूलन महत्व रखता है। उन्होंने आतंकवाद को बहुपक्षीय कार्रवाई और सक्रिय जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को अंतिम रूप देने और ग्रहण करने के माध्यम से शामिल करने का भी आह्वान किया।

		परमाणु अप्रसार के प्रयास।		
यूएस का दौरा 26-30 सितम्बर, 2014		प्रधानमंत्री ने 26-30 सितम्बर, 2014 के दौरान द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा के निमंत्रण पर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी का दौरा किया और दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक थी। चलें साथ साथ: हम एक साथ आगे जाएं' और एक संयुक्त वक्तव्य के विषय पर एक संकल्पना वक्तव्य, उस दूरदृष्टि का एहसास करने के लिए ठोस तरीके को दर्शाती है, जो सितंबर 2014 में अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जारी किए गए थे।		
म्यांमार का दौरा 11-13 नवम्बर, 2014		आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दौरा किया। हाशिए पर, प्रधानमंत्री ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू थेन सेन के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं में चर्चा हुई। लोकतंत्र के आपसी हित के मुद्दों पर राष्ट्रीय लीग के नेता, डाव आंग सान सू क्यी के साथ चर्चाएं भी आयोजित की गईं।		
ऑस्ट्रेलिया का दौरा, 14-18 नवम्बर 2014		ब्रिस्बेन में आयोजित जी -20 शिखर सम्मेलन में भाग लेना तथा ऑस्ट्रेलिया के लिए द्विपक्षीय का दौरा। 15-16 नवंबर 2014 को ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में 9वें जी - 20 शिखर सम्मेलन, ब्रिस्बेन में प्रधानमंत्री ने 9वें जी - 20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया । वैश्विक अर्थव्यवस्था, मूलसंरचना निवेश, कर चोरी, रोजगार सृजन, कार्यबल में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी, ऊर्जा, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आदि सहित शिखर सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।	i) सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण पर करार ii) कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। iii) सामाजिक सुरक्षा पर करार iv) पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन। v) नारकोटिक्स यातायात प्रतिरोध तथा विकासशील पुलिस सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	

		शिखर सम्मेलन के समापन पर एक लीडर्स 'विज्ञप्ति तथा इबोला पर नेताओं के ब्रिस्बेन वक्तव्य जारी किए गए थे। भारत जी -20 प्रारूप के तहत सहयोग को आगे गहरा तथा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।		
फिजी का दौरा 19 नवम्बर, 2014.		प्रधानमंत्री ने 19 नवम्बर 2014 को फिजी का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने लगभग 33 वर्षों के अंतराल के बाद फिजी में दौरा आयोजित किया। प्रधानमंत्री ने फिजी प्रधानमंत्री, बैनीमारामा से मुलाकात की, फिजी संसद को संबोधित किया, फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सिविल सोसाइटी से मुलाकात की और फिजी के भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। भारत मानव संसाधन विकास / आईटी / सौर ऊर्जा / कृषि / नारियल प्रसंस्करण, आदि के क्षेत्र में फिजी को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय समझबूझ और सहयोग को इस दौरे में आगे बढ़ाया। दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री ने 14 प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के नेताओं के साथ "भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग के लिए फोरम" की पहली शिखर स्तरीय बैठक (एफआईपीआईसी) का आयोजन किया। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन पर हमारे साझे हितों और चिंताओं को साझा करने, विकास के लिए सहायता प्रदान करने और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए पीआईसीएस के साथ अपने संबंधों को आगे मजबूत बनाने के लिए भारत को अवसर प्रदान किया गया। भारत द्वारा शिक्षा, आईटी, जलवायु परिवर्तन (सौर ऊर्जा), स्वास्थ्य, आगमन पर ई-पर्यटक वीजा के अनुदान की महत्वपूर्ण छोटी परियोजनाओं आदि में द्विपक्षीय सहायता में वृद्धि के क्षेत्रों	दौरे के दौरान, 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे (1) कूटनीतिक मिशन के निर्माण के लिए भूमि का निर्धारण; (2) फिजी के रेरवाई चीनी मिल में एक सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए 70 मिलियन अमेरिका डॉलर पर ऋण रेखा; तथा (3) कूटनीतिज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	

		में पीआईसीएस को सहायता प्रदान की जाती है।		
नेपाल का दौरा 25-27 नवम्बर 2014		नेपाल में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा की गई थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों को आयोजित किया गया।	**1.** नेपाल पुलिस अकादमी पर समझौता ज्ञापन **2.** पर्यटन पर समझौता ज्ञापन **3.** पारंपरिक दवाओं पर समझौता ज्ञापन **4.** युवा विनिमय पर समझौता ज्ञापन **5.** नेपाल के लिए ऋण के नए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिटलाइन के समझौते **6.** मोटर वाहन करार **7.** 900 मेगावाट अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना विकास समझौते **8-10.** (i) अयोध्या - जनकपुर, (ii) काठमांडू-वाराणसी, तथा (iii) लुम्बिनी-बोधगया के बीच ट्विन सिटी के समझौते	
यूएस का दौरा 26-30 सितम्बर 2014		प्रधानमंत्री ने 26-30 सितम्बर 2014 से अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान 27 सितंबर 2014 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 वें सत्र के उच्च स्तर के खंड (एचएलएस) में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजरायल, अमेरिका सहित 69 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर राज्य / सरकारों के विभिन्न प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, संयुक्त राष्ट्र शांति, सतत विकास लक्ष्यों, आतंकवाद सहित मुद्दों पर चर्चा की।		
सेशेल्स का दौरा 10-11 मार्च 2015		द्विपक्षीय दौरा	i) हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन ii) अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र पर समझौता ज्ञापन iii) धारणा द्वीप पर सुविधाओं की तैनाती के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन iv) नेविगेशन चार्ट की बिक्री पर प्रोटोकॉल	
मॉरीशस का दौरा 11-12 मार्च 2015		मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि	i) अगलेगा द्वीप में समुद्र और वायु परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन	

			ii) पारंपरिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन iii) भारत से आम के आयात के लिए प्रोटोकॉल iv) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के विस्तार v) महासागर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	
श्रीलंका का दौरा, 13 मार्च, 2015		श्रीलंका में राजनीतिक घटनाक्रम सहित आपसी हित के मुद्दों की विस्तृत रेंज	i) सीमा शुल्क सहयोग पर समझौता ii) कूटनीतिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकताओं की छूट पर करार iii) युवा विकास के क्षेत्र में समझौता सहयोग ज्ञापन iv) मतारा के रुहुना विश्वविद्यालय में रवीन्द्रनाथ टैगोर सभागार के निर्माण पर समझौता ज्ञापन	
सिंगापुर का दौरा, 29 मार्च 2015		सिंगापुर के संस्थापक जनक और प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू के राजकीय अंतिम संस्कार सेवा में भाग लेने के लिए।		
फ्रांस का दौरा, 9-12 अप्रैल, 2015		भारत और फ्रांस जैसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रेलवे, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यटन, मानव आदान प्रदान, अक्षय ऊर्जा तथा ऐतिहासिक स्मारकों की ट्विनिंग आदि के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित यात्रा के दौरान 19 समझौतों / समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।	माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 19 (उन्नीस) समझौतों / समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 1. एल एंड टी और अरेवा के बीच समझौता ज्ञापन 2. एनपीसीआईएल और अरेवा के बीच पूर्व - अभियांत्रिकी समझौते 3. मेघा ट्रॉपिक्स पर इसरो और सीएनईएस के बीच समझौता ज्ञापन 4. भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से अधिक का-बैंड प्रचार प्रयोग के लिए इसरो, सीएनईएस और ओनेरा के बीच समझौता ज्ञापन 5. इसरो और राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन फ्रांसीसी केन्द्र (सीएनईएस) के बीच कार्यक्रम 6. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई),	अप्रैल 2015 में फ्रांस के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ओलांद ने आतंकवाद मूल संरचना को गिराने आतंकवादियों को सुरक्षित स्थान देने की मनाही, अपराधियों तथा आतंकवादी हमलों की षडयंत्र योजना बनोन वालों को कानून के दायरे में लाने और इस क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं मजबूत करते हुए आतंकवाद

			भारत सरकार और पारिस्थितिकीय मंत्रालय सतत विकास और ऊर्जा, फ्रांस सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) 7. रेल और फ्रांसीसी राष्ट्रीय रेलवे (एस एन सी एफ) के भारत मंत्रालय के बीच रेलवे प्रोटोकॉल 8. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तपोषण के लिए एएफडी (ईईएसएल) के साथ गारंटी करार 9. सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था 10. पर्यटन पर आशय पत्र 11. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और राष्ट्रीय निवारक पुरातत्व अनुसंधान संस्थान (आईएनआरएपी) के बीच आशय पत्र (एलओआई) / समझौता ज्ञापन 12. पेरिस, फ्रांस में राष्ट्रीय वास्तुकला संस्थान, और दिल्ली के योजना और वास्तुकला स्कूल के बीच समझौता ज्ञापन। 13. भारतीय विरासत शहरी नेटवर्क फाउंडेशन (आईएचसीएन) नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ टौंस एंड रेगिओन्स ऑफ़ आर्ट एंड हिस्ट्री एंड सिटीज है सेफगार्डेड एंड प्रोटेक्टेड सेक्टर्स ('अन्वेष') के बीच समझौता ज्ञापन 14. आयुष मंत्रालय और स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के बीच आयुर्वेद पर आशय पत्र 15. उदयपुर पैलेस और शैटॉ चमबोर्ड के बीच दोहरे करार। 16. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), भारत और राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता आयोग (आयोग राष्ट्रीय प्रमाणन प्रोफेशनल - सीएनसीडी) के बीच समझौता ज्ञापन। 17. भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान फ्रांसीसी केंद्र (सीएनआरएस) के बीच	से निपटने पर बल दिया। राष्ट्रपति ओलांद ने मुंबई हमले के आरोपी जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया।

			विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। 18. भारत में एक राष्ट्रीय समुद्री जीवविज्ञान संस्थान और जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए सहयोग पर भारत और सीएनआरसी और विश्वविद्यालय पियरे एट मैरी क्यूरी के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (यूपीएमसी) के बीच समझौता ज्ञापन। 19. युवा कार्य मंत्रालय और भारतीय खेल तथा खेल, युवा कार्य, सार्वजनिक शिक्षा और समुदाय के जीवन के फ्रेंच मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	
जर्मनी का दौरा, 12-14 अप्रैल, 2015		हनोवर मेसी के उद्घाटन के लिए, जिसमें भारत भागीदार देश था। प्रधानमंत्री और कुलपति मार्केल ने विचार विमर्श द्विपक्षीय आर्थिक कार्यसूची पर केंद्रित किया। दोनों पक्षों ने विनिर्माण, कौशल विकास, शहरी विकास, पर्यावरण, रेलवे, नदियों की सफाई, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित सहयोग के लिए आपसी क्षेत्रों की पहचान की। उन्होंने असैन्य परमाणु सहयोग, आतंकवाद के संदर्भ में रक्षा सहयोग, खुफिया आदान-प्रदान, निर्यात नियंत्रण सहित कई मुद्दों की व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री और चांसलर मार्केल ने भारत - यूरोपीय संघ बीटीआईए (व्यापक आधार वाले व्यापार एवं निवेश समझौते) के प्रारंभिक निष्कर्ष सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।	प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 3 (तीन) आशय पत्रों / जेडीआई पर हस्ताक्षर किए गए। (i) इंडो-जर्मन सौर भागीदारी पर जर्मनी सरकार और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संघीय मंत्रालय के बीच आशय पत्र (ii) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, भवन और रिएक्टर सुरक्षा के जर्मन संघीय मंत्रालय के बीच सतत शहरी विकास पर आशय की संयुक्त घोषणा; तथा (iii) इंडो-जर्मन कौशल विकास परियोजना पर आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय, सरकार जर्मनी और कौशल विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार के उद्यमिता के बीच आशय पत्र ।	
कनाडा का दौरा, 14-16 अप्रैल 2015			अप्रैल 2015 को कनाडा में प्रधानमंत्री दौरे के साथ ही निम्नलिखित समझौता ज्ञापन और आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।	

			खरीद और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और सीएएमईसीओ इंक के बीच 2015-2020 के दौरान मे. सीएएमईसीओ इंक कनाडा से यूरेनियम ओर कंसन्ट्रेट की खरीद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी के बीच बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग। रेल मंत्रालय और परिवहन विभाग, कनाडा के बीच रेलवे के तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन। रोग उन्मूलन और मस्तिष्क बचाव की पहल में सहयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ग्रैंड चैलेंजिस कनाडा फॉर इम्प्लीमेंटेशन के बीच आशय पत्र। उड्डयन के लिए कौशल विकास - राष्ट्रीय कुशल विकास निगम (एनएसडीसी) और सेनेका कॉलेज, टोरंटो के बीच गैर तकनीकी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। उड्डयन क्षेत्र के लिए कौशल विकास - एनएसडीसी और कैनेडोर कॉलेज, नॉर्थ बे, ओंटारियो के बीच तकनीकी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग कॉलेज, लिनसवे के बीच पेयजल क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। खेल क्षेत्र (त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन – बो वैली कॉलेज, अलबर्टा - कैमोसुन कॉलेज, विक्टोरिया और एनएसडीसी) में कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	

			एनएसडीसी और एल्गोक्विन कॉलेज, ओटावा के बीच ऑटोमोटिव और निर्माण के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और न्यू कैलेडोनिया कॉलेज, प्रिंस जॉर्ज बीसी के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और अल्बर्टा प्रौद्योगिकी दक्षिण संस्थान, अल्बर्टा के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और डरहम कॉलेज, टोरंटो के बीच ऑटोमोटिव और कृषि क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और फैनश्वे कॉलेज, लंदन, ओंटारियो के बीच पोशाक और वस्त्र क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और कैमोसुन कॉलेज, विक्टोरिया, बीसी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और बीच एनएसडीसी और आईसीटीसी - सीटीआईसी, ओटावा के बीच आईटी दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्षेत्र कौशल परिषद पर समझौता ज्ञापन। एनएसडीसी और इको कनाडा, कैलगरी, अलबर्टा के बीच हरित नौकरियां के लिए क्षेत्र कौशल परिषद पर समझौता	

			ज्ञापन। एनएसडीसी और कॉलेजों और संस्थानों, कनाडा और कॉलेज तथा संस्थान, कनाडा (सामुदायिक कॉलेज के एसोसिएशन) के बीच कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	
चीन का दौरा 14-16 मई 2015		• प्रधानमंत्री ने 14-16 मई 2015 को चीन का दौरा किया। • भारत-चीन संबंधों में 'मील के पत्थर' रूप में एक महत्वपूर्ण यात्रा को अंकित किया। प्रधानमंत्री का स्वागत शीआन में राष्ट्रपति शी ने किया, जो उनके साथ एक बौद्ध मंदिर गए और एक भोज की मेजबानी की तथा प्रधान मंत्री के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। यह चीन की ओर से एक 'विशेष सद्भावना' थी। प्रधानमंत्री ने बीजिंग में प्रीमियर ली केकियांग के साथ प्रतिबंधित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का आयोजन किया। • स्वर्ग के मंदिर में एक संयुक्त योग-ताइची प्रदर्शन के लिए प्रीमियर ली के साथ प्रधानमंत्री गए। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री वांग यी की उपस्थिति में, सिंघुआ विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया, उन्होंने चीनी नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीजा की घोषणा की है। • दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। खुलकर और स्पष्ट तरीके से आपसी महत्व और हित के उठाए गए और चर्चा किए गए सहयोग और विभिन्न मुद्दों दो पक्षों के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए बहुत उपयोगी बातचीत की थी। • चेंगदू और चेन्नई आदि में सीजी रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खनन, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा,	1. गुआंगज़ौ में जियांग्ज़ी प्रांत शामिल करने के लिए चेंगदू और चेन्नई में भारत गणराज्य के महा वाणिज्य दूतावास तथा कांसुलर जिले के विस्तार में वाणिज्य दूतावास जनरल की स्थापना पर प्रोटोकॉल। 2. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 3. अहमदाबाद / गांधीनगर गुजरात में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना में सहयोग पर कार्य योजना 4. व्यापार वार्ता में सहयोग के लिए एक सलाहकार तंत्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन 5. भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन 6. रेलवे क्षेत्र में वृद्धि सहयोग पर कार्य योजना (2015-2016) 7. शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन 8. खनन और खनिज क्षेत्र के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 9. अंतरिक्ष सहयोग को रेखांकित (2015-2020) 10. भारतीय रेपसीड भोजन के आयात पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों पर प्रोटोकॉल 11. प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 12. पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता	यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया "दोनों पक्ष आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की मजबूती से निंदा करते हैं और आतंकवाद का मुकाबला करने पर सहयोग करने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध हैं। वे सहमत है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है और उन्होंने संयुक्त अधिकार पत्र और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संगत सिद्धांतों और प्रयोजनों के अनुसार सभी देशों तथा इकाइयों से निष्ठा पूर्ण तरीके से आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ने और उनके निधिकरण समाप्त करने एवं आतंकवादियों के सीमा पार आगमन को रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय पर वार्ता के शीघ्र निष्कर्ष का आह्वान

		पर्यटन, लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान, स्थापना जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने के लिए दोनों पक्षों के 24 सहमति पत्रों / करार पर हस्ताक्षर किए। • इसके अलावा, शंघाई में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि के लिए 26 व्यापार समझौतों / के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। • प्रधानमंत्री का स्वागत शीआन में राष्ट्रपति शी ने किया, जो उनके साथ एक बौद्ध मंदिर गए और एक भोज की मेजबानी की तथा प्रधान मंत्री के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। • प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान बीजिंग में दोनों पक्षों के 1 भारत-चीन के राज्य / क्षेत्रीय नेताओं 'फोरम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने शंघाई में फूडान विश्वविद्यालय में गांधीवादी और भारतीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। युन्नान मिंजु विश्वविद्यालय, कुनमिंग में एक योग कॉलेज की स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षों पर हस्ताक्षर किए।	13. भारत-चीन की थिंक टैंक फोरम की स्थापना पर समझौता ज्ञापन 14. भारत सरकार की नीति आयोग और डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, चीन के जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के बीच समझौता ज्ञापन 15. भूकंप विज्ञान और भूकंप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग के विषय में समझौता ज्ञापन 16. महासागर विज्ञान, महासागर प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय विज्ञान और हिमांकमंडल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 17. भूविज्ञान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, भारत और चीन गणराज्य का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, चीन के जनवादी गणराज्य की भूमि और संसाधन मंत्रालय के बीच वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन 18. राज्यों / प्रांतीय नेताओं 'फोरम की स्थापना पर समझौता ज्ञापन 19. भारत गणराज्य के कर्नाटक राज्य सरकार और चीन के सिचुआन पीपुल्स गणराज्य की प्रांतीय सरकार के बीच सिस्टर-स्टेट / प्रांत संबंध की स्थापना पर समझौता 20. चेन्नई, भारत गणराज्य और चूंगचींग, चीन के जनवादी गणराज्य के बीच सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर समझौता 21. हैदराबाद, भारत गणराज्य और क़िंगदाओ, चीन के जनवादी गणराज्य के बीच सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर समझौता 22. औरंगाबाद, भारत गणराज्य और दुनहुआंग, चीन के जनवादी गणराज्य के बीच सिस्टर सिटी संबंधों की	किया है।"

			स्थापना पर समझौता 23. गांधीवादी और भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और फूडान विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन 24. एक योग कॉलेज की स्थापना पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और युन्नान मिंजु विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन	
मंगोलिया के लिए यात्रा 17 मई 2015		• प्रधानमंत्री ने 17 मई 2015 को मंगोलिया का दौरा किया। यह मंगोलिया के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की अब तक की पहली यात्रा थी और यह उस साल में हुई जिसमें हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के हमारे 60 सालों और मंगोलियाई लोकतंत्र के 25 सालों का उत्सव मना रहे हैं। इसलिए वहां लोकतंत्र और बौद्ध संबंधों पर अधिक बल दिया जा रहा है जो हमारे पास हैं। • संबंध को एक 'सामरिक साझेदारी' के लिए उन्नत बनाया गया था और संयुक्त वक्तव्य सहित 14 दस्तावेजों पर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। • प्रधानमंत्री ने उलानबातर में गनडन मठ के लिए बोधगया में पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। • प्रधानमंत्री ने मंगोलियाई संसद को संबोधित किया जो मंगोलिया के संसदीय अध्यक्ष की ओर से एक विशेष संकेत के रूप में एक सप्ताहांत पर खोला गया था। • प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बैठकों, दोपहर के भोजन और रात के भोजन पर मंगोलियाई नेतृत्व के साथ बातचीत की। विचार विमर्श में रक्षा और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच	1.भारत-मंगोलिया सामरिक भागीदारी के लिए संयुक्त वक्तव्य 2.हवाई सेवा करार 3.सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि 4.पशु स्वास्थ्य और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता 5.चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 6.मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन 7.मंगोलिया में भारत-मंगोलिया संयुक्त मैत्री स्कूल की स्थापना पर समझौता ज्ञापन 8. वर्ष 2015-2018 के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यक्रम 9.भारत गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और मंगोलिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन 10. भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और मंगोलिया के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, "दोनों प्रधानमंत्रियों ने नोट किया है कि हाल के वर्षों में प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का प्रसार सभी मानवता के लिए खतरा बन गया है और दोहरे मापदंड या चयनात्मकता के बिना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की वैश्विक संकल्प और सहकारी उपायों की आवश्यकता है। वे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाने के लिए एक साथ काम करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए सहमत हुए। प्रधानमंत्रियों ने आशा व्यक्त की कि आतंकवादियों के लिए सभी सुरक्षित आश्रय स्थलों को देरी के बिना उनका सफाया किया जाएगा।"

		संपर्कों सहित सहयोग के क्षेत्रों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया। • दोनों प्रधानमंत्री संसदीय सहित संस्थागत संपर्कों साथ ही सरकारी बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सहमत हुए जिसमें मौजूदा तंत्र जैसे दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों और संचार के अन्य सभी चैनलों के बीच सहयोग संबंधी संयुक्त समिति, विचार-विमर्श नीति के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध, आपसी हित और चिंता के अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर नियमित बातचीत शामिल है। • भारत अपनी क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए मंगोलिया के लिए 1 अरब अमेरीकी डालर की एक क्रेडिट लाइन का विस्तार करने के लिए सहमत है और मंगोलियाई अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्सासहन के रूप में इसका स्वागत किया गया। यहाँ डेयरी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक प्रस्ताव भी था जहाँ भारत द्वारा मवेशियों के मौजूदा दोहन के लिए, मंगोलिया में डेयरी उत्पादों के प्रशिक्षण और समर्थन के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का विस्तार किया जाएगा। • खनन क्षेत्र में सहयोग भी चर्चा के प्रमुख मुद्दों में से एक था। • विचार विमर्श एक बहुत दोस्ताना माहौल में हुआ और इस यात्रा के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के लिए विश्वास और समर्थन को उच्च स्तर द्वारा चिह्नित किया गया था। • प्रधानमंत्री ने मिनी नादम त्योहार में भाग लिया जिसमें तीरंदाजी, कुश्ती और घुड़सवारी के मंगोलियाई पारंपरिक खेल का प्रदर्शन किया गया। मंगोलिया के	11.भारत गणराज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और मंगोलिया के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन 12.सीमा चौकसी में सहयोग बढ़ाने, पुलिस और निगरानी के लिए समझौता ज्ञापन 13.रेडियोथेरेपी सिमुलेटर सहित भाभाट्रॉन - II टेली-चिकित्सा इकाई को उपहार देने के लिए समझौता ज्ञापन 14.भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और मंगोलिया के विदेश मंत्रालय के राजनयिक अकादमी के विदेश सेवा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन	

		प्रधानमंत्री ने स्थानीय रिवाज के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को एक बछड़ा भेंट किया। • प्रधानमंत्री ने मंगोलियाई और भारतीय नागरिकों दोनों के 6000 से अधिक लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। जीवांत समूह की कला से योग के प्रति उत्साहित करने के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सभी आयु समूहों के मंगोलियाई ने भी इस अवसर पर कुछ पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया।		
कोरिया के लिए यात्रा 18-19 मई 2015		सहयोग बढ़ाने के लिए एक दृश्य के साथ राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक विचार विमर्श आयोजित किया गया था। भारत-कोरिया के संबंध 'विशेष सामरिक भागीदारी' के लिए उन्नत बनाया गया था। '2+2' संवाद स्थापित किया गया था जिसे भारत और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं के बीच विचार-विमर्श के लिए औपचारिक रूप दिया गया। संयुक्त कार्य समूह जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। सहयोग स्मार्ट ग्रिड, इस्पात क्षेत्र, समुद्री परिवहन आदि सहित क्षेत्रों में लगाया जा रहा है।	1. दोहरे कराधान से बचाव अभिसमय 2. ऑडियो विजुअल सह-उत्पादन 3. युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 4. भारत और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन 5. समुद्री परिवहन और रसद में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन 6. बिजली विद्युत विकास में सहयोग और नए ऊर्जा उद्योग पर समझौता ज्ञापन 7. सड़क परिवहन और राजमार्ग में सहयोग की रूपरेखा	यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है: "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति और स्थिरता के समक्ष बढ़ा रहे और विकसित खतरे को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं ने अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का उन्मूलन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और इस चुनौती से निपटने के लिए मिलकर कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आमंत्रित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय पर वार्ता के शीघ्र निष्कर्ष के लिए कहा। उन्होंने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने और बुनियादी रूपरेखा को खत्म करने,

				आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्तपोषण बाधित, और आतंकवादियों को सीमा पार से आंदोलन को रोकने, संगत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने के लिए, साथ ही हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के प्रयासों को बढ़ाने के द्वारा भी इन्हें शामिल करने की आवश्यकता को मान्यता दी है। उन्होंने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से कार्य करने के लिए सभी राज्यों का आह्वान किया।"
बांग्लादेश के लिए यात्रा, 06-07 जून, 2015		राजकीय की यात्रा जिसके दौरान 22 समझौता ज्ञापनों / करार पर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर / विचार विमर्श किया।	i) भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 और भूमि सीमा करार के 2011 के प्रोटोकॉल के बारे में अनुसमर्थन के साधन के विनिमय के लिए प्रोटोकॉल। ii) भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 और भूमि सीमा करार के 2011 के प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों पर पत्रों के आदान प्रदान। iii) बांग्लादेश की सरकार को भारत सरकार द्वारा 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की एक नई रेखा (एलओसी) के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन। iv) भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय शिपिंग पर करार। v) अंतर्देशीय जलमार्ग ट्रांजिट और व्यापार	

			(पीआईडब्ल्यूटीटी) (नवीनीकरण) पर प्रोटोकॉल। vi) भारत के लिए और उनकी ओर से माल की आवाजाही के लिए चित्तगोंग और मोंगला बंदरगाहों के इस्तेमाल पर समझौता ज्ञापन vii) द्विपक्षीय व्यापार करार (नवीनीकरण)। viii) बांग्लादेश में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन। ix) मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और बांग्लादेश स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (बीएसटीआई) के बीच द्विपक्षीय सहयोग करार। x) ब्लू अर्थव्यवस्था और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन। xi) भारत और बांग्लादेश : ढाका-शिलांग-गुवाहाटी बस सेवा के बीच मोटर वाहनों के यात्री यातायात के विनियमन पर करार। xii) भारत और बांग्लादेश: कोलकाता-ढाका - अगरतला बस सेवा के बीच मोटर वाहनों के यात्री यातायात के विनियमन पर करार। xiii) वर्ष 2015-2017 के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (नवीनीकरण) xiv) भारत और बांग्लादेश के तटरक्षकों के बीच समझौता ज्ञापन xv) मानव तस्करी की रोकथाम के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन xvi) नकली नोटों की तस्करी और संचलन की रोकथाम	

			पर समझौता ज्ञापन xvii) जामिया मिलिया इस्लामिया, भारत और राजशाही विश्वविद्यालय, बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन xviii) शिक्षा सहयोग के लिए आशय का वक्तव्य xix) बंगाल की खाड़ी के समुद्र विज्ञान पर संयुक्त अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारत, और ढाका विश्वविद्यालय, बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन xx) बांग्लादेश के लिए 70000 सुधार कुक स्टोव की स्थापना के लिए एंडोवमेंट फॉर क्लाइमेट चैंज इन साउथ एशिया (आईईसीसी-एसए) के लिए भारत बंदोबस्ती के तहत भारत सरकार से सहायता अनुदान से संबंधित समझौता ज्ञापन xxi) एलआईसी द्वारा बांग्लादेश में परिचालन शुरू करने के लिए अध्यक्ष के लिए बांग्लादेश की बीमा विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (आईडीआरए), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से सहमति-पत्र xxii) इंटरनेट के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ को पट्टे पर देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और बांग्लादेश सबमरिन केबल कंपनी लिमिटेड (बीएससीसीएल) के बीच करार	
उज़्बेकिस्तान के लिए यात्रा 06-07 जुलाई 2015		प्रधानमंत्री ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार विमर्श के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा का आयोजन किया।	i. पर्यटन के क्षेत्र में करार ii. विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग पर प्रोटोकॉल iii. सांस्कृतिक सहयोग पर कार्यक्रम	दोनों पक्ष आतंकवाद पर उज़्बेकिस्तान-भारत संयुक्त कार्य समूह की रूपरेखा के तहत शामिल दो देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विशेष सेवाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने पर सहमत हुए।

कजाकिस्तान के लिए यात्रा 07-08 जुलाई 2015		प्रधानमंत्री ने कजाख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। नेताओं ने संपर्क परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए और भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि मशीनरी, खनन और संपर्क के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए।	i. सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर करार ii. रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग पर करार iii. भौतिक संस्कृति और खेल पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन iv. रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन v. प्राकृतिक यूरेनियम की बिक्री और खरीद के लिए संविदा काजाटोम्प्रोम और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच केंद्रित है।	दोनों पक्षों ने नियमित रूप से अंतर-एजेंसी परामर्श और आतंकवाद पर संयुक्त कार्य समूह की बैठकों के महत्व पर प्रकाश डाला। नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक अभिसमय को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है।
8-9 जुलाई 2015 को रूस के लिए यात्रा Visit to Russia on 8-9 July 2015		प्रधानमंत्री ने ऊफ़ा, रूस में 08-09 जुलाई 2015 को आयोजित 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र सुधार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार, विश्व व्यापार संगठन, जी -20, क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम, आतंकवाद, नए विकास बैंक (एनडीबी), ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) आईसीटी में सहयोग और अंतर-ब्रिक्स सहयोग से संबंधित अन्य मुद्दों पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा के मुद्दों को शामिल किया। 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में सांस्कृतिक सहयोग पर एक करार, एक संयुक्त ब्रिक्स वेबसाइट के निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन पर और एनडीबी के साथ सहयोग पर ब्रिक्स अंतर-बैंक तंत्र के तहत एक समझौता ज्ञापन शामिल है। ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी के लिए कार्यनीति भी ऊफ़ा शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी।	7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में सांस्कृतिक सहयोग पर एक करार, एक संयुक्त ब्रिक्स वेबसाइट के निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन पर और एनडीबी के साथ सहयोग पर ब्रिक्स अंतर-बैंक तंत्र के तहत एक समझौता ज्ञापन शामिल है। ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी के लिए कार्यनीति भी ऊफ़ा शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी।	वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाक्रम और आतंकवाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कार्यसूची मद इसमें शामिल थे। ब्रिक्स नेताओं ने अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की घोर निन्दा की बात दोहराई और जोर दिया कि आतंकवाद के किसी भी कार्य को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वह वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक, नस्ली, जातीय, या किसी भी अन्य औचित्य पर आधारित है।
तुर्कमेनिस्तान के लिए यात्रा 10-11 जुलाई		प्रधानमंत्री तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की।	i) भारतीय पीएसयू आरसीएफ और तुर्कमेन राज्य चिंता का विषय 'तुर्कीमेहिमिया' के बीच रासायनिक उत्पादों की आपूर्ति पर समझौता ज्ञापन	नेताओं ने अवलोकन किया कि हाल के वर्षों में प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का

2015			ii. तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन iii) खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता iv. 2015-17 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग कार्यक्रम v) योग और पारंपरिक दवा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन vi. पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन vii. रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर करार	तेजी से प्रसार आज सबसे गंभीर वैश्विक खतरों में से एक बन गया है। नेताओं ने विभिन्न सुरक्षा खतरों से निपटने में चल रहे सहयोग को गहरा करने की संकल्प की है और आतंकवाद जैसे सीमा पार के खतरों के खिलाफ प्रयासों को बढ़ाने के लिए सहमत हुए।
किर्गिज गणराज्य के लिए यात्रा 11-12 जुलाई 2015		i. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और किर्गिज गणराज्य अर्थव्यवस्था मंत्रालय (मानकीकरण केंद्र और अंतरिक्ष-विज्ञान / सीएसएम) के बीच समझौता ज्ञापन ii. भारत निर्वाचन आयोग और चुनाव के लिए केंद्रीय आयोग और किर्गिज गणराज्य के जनमत संग्रह के बीच चुनाव के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन iii. संस्कृति, कला, युवा, खेल और मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और किर्गिज गणराज्य सरकार के बीच समझौता।. iv. रक्षा सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और किर्गिज गणराज्य सरकार के बीच करार	प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। नेताओं ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। वे भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने किर्गिज प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई जहां दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने किर्गिज अध्यक्ष से मुलाकात की और लोगों के प्रतिनिधियों के बीच अधिक से अधिक बातचीत के लिए दोनों देशों के संसद के सदस्यों द्वारा दोनों देशों के सांसदों और यात्राओं के आदान-प्रदान के बीच सहयोग पर चर्चा की।	नेता ''अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अन्य अपराधों का मुकाबला'' पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर शीघ्रता से विचार करने के लिए सहमत हुए।"
ताजिकिस्तान के लिए यात्रा 12-13 जुलाई		प्रधानमंत्री ने ताजिक राष्ट्रपति के साथ प्रतिबंधित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का आयोजन किया। बैठकों के दौरान नेताओं ने व्यापार, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य,	i. 2016-18 की अवधि के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र मं सहयोग कार्यक्रम	नेताओं ने आतंकवाद से मुकाबले पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के ढांचे में

2015		कृषि और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।	ii. ताजिकिस्तान के 37 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए मौखिक नोट का आदान-प्रदान	आधिकारिक स्तरीय बातचीत को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया और जेडब्ल्यूजी की एक प्रारंभिक बैठक बुलाई।
संयुक्त अरब अमीरात के लिए यात्रा 16-17 अगस्त 2015		द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर चर्चा की गई थी।	एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।	संयुक्त अरब अमीरात के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा और विरोध किया तथा आतंकवाद का मुकाबला संचालन, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत की प्रस्तावित व्यापक अभिसमय को अपनाने के लिए एक साथ कार्य करने और आतंकवाद, कट्टरता और विक्षुब्ध सामाजिक सद्भाव के लिए साइबर के उपयोग पर रोकथाम सहित साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं।
आयरलैंड के लिए यात्रा 23 सितंबर 2015		भारत के प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के मार्ग में 23 सितंबर, 2015 को आयरलैंड का दौरा किया। प्रधानमंत्री और आयरलैंड के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के लिए ध्यान केंद्रित बिंदु - द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि,		प्रधानमंत्री ने एयर कनिष्क बम विस्फोट में मारे गए लोगों के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए आयरलैंड की सरकार को

		शिक्षा, पर्यटन और आतंकवाद सहित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, संयुक्त राष्ट्र सुधारों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्थाएं।		धन्यवाद दिया। भारत और आयरलैंड दोनों आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए सहमत हुए।
24-28 सितंबर 2015 को अमेरिका के लिए यात्रा		प्रधानमंत्री ने 24-26 और 28 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 70वें सत्र के उच्च स्तर खंड (एचएलएस) में भाग लिया। उन्होंने 25 सितंबर को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 26 सितंबर को जी-4 शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की और 28 सितंबर को शांति स्थापना पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका, फ्रांस, मिस्र, बांग्लादेश, गुयाना, भूटान, मोरक्को, नाइजीरिया, जोर्डन, फिलिस्तीन, कतर, मैक्सिको और स्वीडन सहित 70वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर राज्य / सरकारों के विभिन्न प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और आतंकवाद के लिए 2030 एजेंडा जैसे मुद्दों पर आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री 23-28 सितम्बर, 2015 को न्यूयॉर्क और सैन जोस का दौरा किया। सितंबर 2015 को अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के मौके पर निम्नलिखित एमओयू / एलओएल हस्ताक्षर किए गए हैं :	एक दूसरे की पारिस्थितिकी प्रणालियों का इस्तेमाल करके उद्यमिता, अनुसंधान, शिक्षा और व्यवसायों पर आधारित उन्नत विज्ञान के लिए भारत-अमेरिका लाइफ साइंस सिस्टर इनोवेशन हब विकसित करने के लिए सेलुलर और आण्विक मंच केंद्र (डीबीटी बायोटेक क्लस्टर, बंगलौर में स्थापित कंपनी का एक खंड) और मात्रात्मक जैव विज्ञान के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट (क्यूबी3) के बीच समझौता ज्ञापन। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत और प्रकाश लैब, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच डीबीटी स्टार कॉलेजों को प्रकाश प्रयोगशालाओं से सोर्सिंग फोल्डस्कोप के लिए है और भारत के कॉलेजों में अन्य कम लागत मापयंत्रण पर संयुक्त अनुसंधान की स्थापना के लिए संभावनाओं पर विचार के लिए आशय पत्र (एलओआई)। भारत और सिलिकॉन वैली में प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का समर्थन करने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी (नैसकॉम) और इंडस उद्यमियों के बीच समझौता ज्ञापन। भारत में तकनीक और उद्यमशीलता प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हास बिजनेस स्कूल के आईआईएम अहमदाबाद सेंटर फॉर इनोवेशन एंड	

			एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) और लेस्टर सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के बीच समझौता ज्ञापन। सीआईआईई के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंट नेटवर्क (एनजीआईएन) सदस्यता लाभ का विस्तार करने और संयुक्त रूप से क्लीनटेक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम अहमदाबाद सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) और लॉस एंजिल्स क्लीनटेक इनक्यूबेटर के बीच समझौता ज्ञापन। सामरिक समर्थन के माध्यम से प्रौद्योगिकी और प्रभावी उद्यमियों का समर्थन करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंट्रेप्रेनियूरशिप (सीआईआईई) और गूगल के बीच समझौता ज्ञापन। भारत फंड पर सहयोग करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) और टाटा ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन, जो भारतीय उद्यमियों को बीज निधि प्रदान करेगा।	
ब्रिटेन के लिए यात्रा 12-14 नवंबर 2015		प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कैमरन ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दो प्रधानमंत्रियों के बुनियादी ढांचे के निर्माण स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और स्वच्छ ऊर्जा सहित भारत के प्रमुख विकास परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल विकास और करीबी भागीदारी के माध्यम से शामिल परमाणु, रक्षा और साइबर क्षेत्रों में गहरी सुरक्षा सहयोग के साथ एक आधुनिक साझेदारी बनाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री कैमरन ने आतंकवाद का मुकाबला करने और वैश्विक निर्णय में भारत को शामिल किए जाने के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में यूएनएससी,	इस यात्रा के दौरान बारह समझौतों की घोषणा नीचे दी गई हैं: (i) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच करार, (ii) ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता ज्ञापन, (iii) होम्योपैथिक चिकित्सा में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एकीकृत चिकित्सा के लिए आयुष मंत्रालय और लंदन अस्पताल के रॉयल बीच समझौता ज्ञापन, (iv) लोक प्रशासन और शासन सुधारों पर सहयोग पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और मंत्रिमंडल कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन, (v) परमाणु ऊर्जा	यूके के लिए प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने सभी प्रपत्रों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा करने के अलावा, संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी पदनाम पर नजदीकी और नियमित रूप से विचार-विमर्श करने के लिए अपने संगत अधिकारियों को निर्देश दिया। दोनों

		बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की सदस्यता और अधिक से अधिक आवाज के माध्यम से बनाने के लिए ब्रिटेन के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। यात्रा के प्रमुख परिणामों में शामिल है (i) दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विवार्षिक वार्ता, (ii) उनके विकास की चुनौतियों को संबोधित करने में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए एक त्रिपक्षीय ढांचे में भारत-ब्रिटेन सहयोग, (iii) मजबूत रक्षा सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला करने में गहरा सहयोग, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों के साथ एक नई रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी का शुभारंभ, (iv) असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता, (v) लंदन में भारत की पहली सरकार समर्थित रुपया बांड जारी करने के इरादे की घोषणा, (vi) आतंकवाद, संपर्क और समुद्री मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नए दक्षिण एशिया वार्ता का शुभारंभ, (vii) विकास की नई द्विवार्षिक मंत्रिस्तरीय वार्ता, (viii) सीईओ फोरम का पुनरुद्धार, (ix) भारत में यूके निवेश के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे निवेश कोष (एनआईआईएफ) के तहत भारत-यूके भागीदारी कोष की स्थापना। वित्त में गहरा सहयोग, आर्थिक और व्यापार नियुक्ति, बुनियादी सुविधाओं, रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित भावी सहयोग के लिए आयोजित विचार विमर्श के परिणामों और क्षेत्रों पहचान करने में दोनों प्रधानमंत्रियों ने नामत: संकल्पना वक्तव्य, ऊर्जा पर संयुक्त वक्तव्य और जलवायु परिवर्तन, रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी और तीसरे देशों में सहयोग के लिए भागीदारी पर आशय वक्तव्य द्वारा जारी	भागीदारी के लिए भारत के वैश्विक केंद्र के साथ सहयोग पर परमाणु ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग और जलवायु परिवर्तन के बीच समझौता ज्ञापन (vi) रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर रेल मंत्रालय और परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (vii) तीसरे देशों में सहयोग के लिए भागीदारी पर आशय वक्तव्य (viii) भारत में यूके की कंपनियों के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली की स्थापना पर भारत और यूके द्वारा संयुक्त घोषणा (ix) कारोबार करने में आसानी पर समझौता ज्ञापन (x) कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन (xi) फसल विज्ञान पर समझौता ज्ञापन (xii) जलवायु परिवर्तन, कृषि, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और टीके के विकास के क्षेत्रों में आशय पत्र	प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान को न्याय के लिए मुंबई में नवंबर 2008 के आतंकवादी हमले के षड्यंत्रकारियों को लाने के लिए भी उनके फोन को दोहराया। दोनों पक्षों ने (i) सीसीआईटी को अंतिम रूप देने और आईएसआईएल, अल कायदा, लश्कर-ए-तैयबा,हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, हक्कानी और संबद्ध समूहों सहित आतंकवादी नेटवर्क के लिए वित्तीय और सामरिक समर्थन को बाधित करने के लिए के संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग की भी पुष्टि की। (ii) आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के लिए उत्कृष्टता और साइबर क्राइम समन्वय केंद्र प्रतिबद्धता का एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की साइबर सुरक्षा और स्थापना में सहयोग के नए रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी में दिखाई देता है।

		संयुक्त वक्तव्य और चार अन्य परिणाम दस्तावेज में परिलक्षित होते हैं। असैन्य परमाणु सहयोग पर 2010 संयुक्त घोषणा का निर्माण, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर एक समझौते पर 12-14 नवम्बर 2015 को ब्रिटेन के लिए माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह दोनों देशों को बिजली, पानी अलवणीकरण, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और चिकित्सा आदि के उत्पादन के लिए परमाणु सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा के उपयोग सहित क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में सहयोग करने के लिए अनुमति देगा।		
15-16 नवम्बर 2015 को तुर्की के लिए यात्रा		प्रधानमंत्री ने 15-16 नवम्बर 2015 को अंटाल्या, तुर्की में 10वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विकास और जलवायु; आतंकवाद और शरणार्थी संकट; वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास और रोजगार और निवेश कार्यनीतियों; उन्नत लचीलापन: वित्तीय नियमन, अंतरराष्ट्रीय कर, भ्रष्टाचार निरोधक, आईएमएफ सुधार; और व्यापार और ऊर्जा सहित शिखर सम्मेलन एजेंडा। गुणवत्तापूर्ण नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रण विज्ञप्ति, श्रम बाजार में युवाओं के बेहतर एकीकरण, रक्षा के प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता और शरणार्थियों तथा विस्थापित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एसएमई की भागीदारी, 5% के लिए वैश्विक औसत प्रेषण लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्धता, कृषि में निवेश, खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने के लिए प्रतिबद्धता, बाजार		आतंकवाद और शरणार्थी संकट पर शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। Terrorism and Refugee Crisis were discussed at the Summit. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जी -20 स्टैंडअलोन वक्तव्य की मुख्य विशेषताओं में सभी कार्य, तरीके और आतंकवाद के तरीकों, पुन: पुष्टि की स्पष्ट निंदा शामिल है, जिसमें आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह के साथ जुड़ा नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र

		पारदर्शिता में सुधार, और छोटे धारक और परिवारिक किसान, ग्रामीण महिलाओं तथा युवाओं पर विशेष ध्यान देना।		की केंद्रीय भूमिका वक्तव्य में मान्यता प्राप्त है। वक्तव्य में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के मानकों के कार्यान्वयन के माध्यम के रूप में सहयोग बढ़ाने और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण चैनलों से निपटने पर जोर दिया।
मलेशिया के लिए यात्रा 21-23 नवम्बर 2015		प्रधानमंत्री ने 21-23 नवंबर 2015 मलेशिया का दौरा किया और 23 नवंबर 2015 को भारत-मलेशिया द्विपक्षीय बैठक सहित 21 नवंबर और 22 नवंबर, 2015 पर क्रमश कुआलालम्पुर में आयोजित आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर बैठकों में भाग लिया। द्विपक्षीय बैठक के दौरान, रक्षा, शिक्षा, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण, संस्कृति, प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण, व्यापार एवं निवेश, आधारभूत संरचना, आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं आदि सहित द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र।	भारत-मलेशिया द्विपक्षीय बैठक के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापन / करारों पर हस्ताक्षर किए गए : (i) 2015-2020 की अवधि के लिए मलेशिया सरकार और मलेशिया सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम समझौता (ii) निष्पादन प्रबंधन, परियोजना वितरण और सरकारी कार्यक्रम व वितरण से संबंधित निगरानी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (iii) साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और साइबर सुरक्षा मलेशिया के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) के बीच समझौता ज्ञापन	
सिंगापुर के लिए यात्रा 23-24 नवंबर 2015		प्रधानमंत्री ने 23-24 नवंबर 2015 को सिंगापुर के लिए अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी। यह यात्रा दोनों के 50वें वर्ष के साथ ही सिंगापुर की स्वतंत्रता और भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों पर हुई।		

		यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया और अवकाश प्राप्त वरिष्ठ मंत्री गोह चोक तोंग से मुलाकात की। चर्चाएँ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मामलों के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में सिंगापुर व्यापार समुदाय और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों के सहयोग के क्षेत्रों पर विस्तार सामरिक साझेदारी पर सामरिक साझेदारी और संयुक्त वक्तव्य पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ कार्यनीतिक स्तर को उठाया गया था। एक उन्नत रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। नारकोटिक्स ड्रग्स, मादक पदार्थ और उनके पूर्ववर्ती में अवैध तस्करी का मुकाबला करने के क्षेत्र में नौ (9) अन्य समझौतों; साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग; हवाई अड्डे के क्षेत्र में सहयोग; शहरी शासन (एससीई) में क्षमता निर्माण; आईसीटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में सहयोग; वर्ष 2015-18 के लिए कार्यकारी कार्यक्रम; कलाकृतियों के ऋण का विस्तार; नीति आयोग और सिंगापुर सहयोग उद्यम; और भारत की नीति आयोग और सिंगापुर की टेमासेक फाउंडेशन सीएलजी के बीच सहयोग करने के लिए आशय पत्र।		

*****

अनुलग्नक- 'ख'

विदेश मंत्री की यात्राएं

विदेश मंत्री द्वारा पिछले एक	किए गए व्यय	आयोजित चर्चाओं और सहयोग के लिए चुने गए क्षेत्रों के विवरण	समझौतों पर हस्ताक्षर किए

वर्ष के दौरान अब तक किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा			
		(क)	
मोरक्को का दौरा 30 जनवरी- 01 फरवरी 2014	भारत सरकार के मिशनों द्वारा यात्रा के साथ शामिल विदेशों में किए गए डेबिट व्यय संबंधित एजेंसियों के लिए किए गए। यह जानकारी एकत्र की जा रही है।	उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र के तीन देशों के भाग में मोरक्को की यात्रा के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मोरक्को, ट्यूनीशिया और सूडान भी शामिल है, जो इस सरकारी यात्रा पर गए। विदेश मंत्री द्वारा मोरक्को की यात्रा पहली बार की जा रही है, अत: यह ऐतिहासिक दौरा था। विदेश मंत्री ने राजा मोहम्मद VI से मुलाकात की और सरकार के प्रमुख (प्रधानमंत्री), प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) के अध्यक्ष, पार्षदों की सभा (ऊपरी सदन) के अध्यक्ष और विदेश मंत्री के साथ बैठकें की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। यात्रा के दौरान भारत और मोरक्को में दो सहयोग समझौतों अर्थात पर्यावरण और समुद्री मत्स्य के क्षेत्रों में हस्ताक्षर किए गए। समुद्री मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग पर पर्यावरण सहयोग और समझौता ज्ञापन पर समझौता। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री के साथ राज्य अतिथि के तौर पर व्यवहार किया था।	
ट्यूनीशिया का दौरा 2-3 फरवरी 2014		1958 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत की ओर से विदेश मंत्री स्तर पर पहली बार द्विपक्षीय यात्रा के लिए ट्यूनीशिया गणराज्य में दो दिन की सरकारी यात्रा पर गए। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोनसेफ मर्जजुकी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री महामहिम श्री मेहदी जोमा और विदेश मंत्री महामहिम श्री मोंगी हम्दी के साथ मुलाकात की। उन्होंने शेख राशिद घंनौची, राष्ट्रपति, एन्नाहडा पार्टी और श्री बेजी कैड एसेब्सी, राष्ट्रपति, निदा ट्यूनिस पार्टी के साथ भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर ट्यूनीशियाई नेतृत्व के लिए भारत की ओर से सरकार को बधाई दी और अवगत कराया। उन्होंने लोकतंत्र और एक टिकाऊ लोकतंत्र की ओर संक्रमण के दौर से अवगत कराया। ट्यूनीशिया के नेतृत्व और सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रगति के लिए भारत की प्रशंसा के साथ उनके संघर्ष में ट्यूनीशिया के लोगों के लिए भारत का हार्दिक समर्थन प्रेषित किया। उन्होंने ट्यूनीशियाई समकक्ष के साथ अपनी बातचीत में कहा कि ट्यूनीशियाई पक्ष ने फार्मास्यूटिकल्स और आईटी क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाओं की खोज के लिए एक जेबीसी की स्थापना का सुझाव दिया है, जहां द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा	

		की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया।	
नीदरलैंड का दौरा 24-25 मार्च2014		24-25 मार्च 2014 को द हेग में नीदरलैंड्स की मेजबानी में तीसरा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन (एनएसएस) के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया।	
भूटान का दौरा, 15-16 जून 2014		पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा विदेश की पहली यात्रा की गई। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री भी थीं। भूटान के साथ हमारे अद्वितीय और विशेष संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।	1. नेहरू-वांग्चुक छात्रवृत्ति के दोहरीकरण (सालाना 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए) 2. ई-पुस्तकालय की स्थापना
नेपाल का दौरा, 25-27 जुलाई 2014		भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक 23 वर्ष बाद आयोजित की गई थी। द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई।	1. नेपाल के तराई क्षेत्र में 2700 उथले नलकूपों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन
म्यांमार पर द्विपक्षीय दौरा अगस्त 11, 2014.		यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष, म्यांमार के विदेश मंत्री यू वुन्ना माउंग ल्विन के साथ विचार विमर्श किया और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, 'विकास सहयोग और कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सीन से मुलाकात की और म्यांमार के निचले सदन के स्पीकर संसद थुरा श्वे मान के साथ भी मुलाकात की।	
सिंगापुर का दौरा 16 अगस्त 2014		भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए स्मारक समारोह का शुभारंभ करने के लिए सिंगापुर का दौरा किया।	
वियतनाम का दौरा 23-26 अगस्त, 2014		विदेश मंत्री ने 24 अगस्त 2014 को क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 23-26 अगस्त, 2014 को हनोई का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वियतनाम की ओर से द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया और वियतनामी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री फाम बिन्ह मिन्ह के साथ थिंक टैंक के आसियान-भारत नेटवर्क (एआईएनटीटी) तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी सह- उद्घाटन किया। उन्होंने क्षेत्रीय राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस क्षेत्र से मिशन के 16 भारतीय प्रमुखों से भी मुलाकात की। वियतनाम की ओर से विचार-विमर्श द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को कवर किया गया।	
बहरीन का दौरा 06-07 सितंबर 2014		बहरीन के नेताओं के साथ आपसी हित के मामलों बैठक के दौरान चर्चा की गई।	प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र और बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड और बहरीन इंडिया सोसाइटी के बीच दो

			समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
यूएई का दौरा 10-12 सितंबर 2014		द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर चर्चा की गई।	
यूएस का दौरा 24 सितंबर- 02 अक्तूबर, 2014		24 सितंबर से 02 अक्टूबर 2014 के बीच अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के अलावा, विदेश मंत्री ने भारत-सीईएलएसी क्वार्टेट विदेश मंत्रियों की बैठक, जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में आम बहस में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1 अक्टूबर को बयान दिया। उन्होंने ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक और भारत-कैरीकॉम विदेश मंत्रियों की मेजबानी की बैठक तथा भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय बैठक, विदेश मंत्रियों ने भारत-सीईएलएसी में भाग लिया, बैठक में सार्क विदेश मंत्रियों के दोपहर का भोज और इसके अलावा ब्रिटेन, सीरिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और राष्ट्रमंडल के महासचिव से उसे समकक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा सहित 29-30 सितंबर को भारत-जीसीसी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक की गई।	
यूके का दौरा अक्तूबर 2014		लंदन में क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस और यात्रा के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड के साथ आपसी हित के मुद्दों पर आयोजित द्विपक्षीय विचार-विमर्श उद्घाटन करने के लिए।	
मारीशस पर दौरा 1-3 नवंबर, 2014		मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए।	
नेपाल का दौरा, 25-27 नवंबर 2014		नेपाल में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा की गई थी। नेपाल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थी।	1. नेपाल पुलिस अकादमी पर समझौता ज्ञापन 2. पर्यटन पर समझौता ज्ञापन 3. पारंपरिक औषधि पर समझौता ज्ञापन 4. युवा आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन 5. नई लाइन के लिए नेपाल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते

			6. मोटर वाहन समझौता 7. 900 मेगावाट अरुण ।।। जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना विकास समझौता 8-10. (i) अयोध्या - जनकपुर (ii) काठमांडू-वाराणसी, और (iii) लुम्बिनी-बोधगया के बीच ट्विन सिटी समझौता।
कोरिया गणराज्य का दौरा 28-30 दिसंबर 2014		विचार-विमर्श के व्यापार एवं निवेशजहाजरानी, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित, संस्कृति आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर आयोजित की गई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। रक्षा, आईटी / आईसीटी, संस्कृति, व्यापार और निवेश क्षेत्रों सहित आदि में जारी सहयोग, समझौता ज्ञापन / समझौता के तत्वावधान पर चर्चा शुरू की जा रही है। नियमित वार्ता तंत्र और आपसी हित के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग की परिकल्पना की गई है।	
तुर्की का दौरा 15-16 जनवरी 2015		कार्य दौरा।	
चीन का दौरा 31 जनवरी-03 फरवरी 2015		यह विदेश मंत्री की चीन की पहली यात्रा थी। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बैठक की थी। राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों, आर्थिक संबंधों और जन-जन संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों पर मुद्दों की पूरी रेंज में चर्चाएं शामिल थीं। उन्होंने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। इस यात्रा के दौरान, इस साल के अंत तक जून की शुरुआत में, नाथू ला के माध्यम से कैलाश मानसरोवर पहुँचने के लिए यात्रा परिचालित करने पर एक समझौता किया गया था। विदेश मंत्री ने चीन में भारत वर्ष यात्रा का शुभारंभ किया जो जन से जन के संपर्क की आपसी समझ को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बीजिंग में उच्च स्तरीय मीडिया फोरम के दूसरा दौरा आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री ने राज्य परिषद मंत्री के सूचना कार्यालय के साथ-साथ इसका भी उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने रूस-भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चीन और रूस शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में हमारी सदस्यता का समर्थन किया गया। रूस और चीन दोनों ही	

		एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) में हमारी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया।	
श्री लंका का दौरा, 15-18 फरवरी 2015		प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी करने के लिए।	
ओमान का दौरा 17-18 फरवरी 2015		द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर चर्चा की गई।	
तुर्कमेनिस्तान का दौरा 7-9 अप्रैल, 2015		विदेश मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और पहल और अधिक ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति और कनेक्टिविटी में द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्री ने अश्गाबात में योग अंतरराष्ट्रीय दिवस की संस्कृति और संगठन के क्षेत्र में सहयोग पर संस्कृति और तुर्कमेनिस्तान के मीडिया के उप प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।	i. अश्गाबात में तुर्कमेन भारत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के उन्नयन पर समझौता ज्ञापन।
इंडोनेशिया का दौरा 21-24 अप्रैल, 2015		60 वें एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन स्मरणोत्सव के संबंध में। उन्होंने सम्मेलन के मौके पर श्री जुसुफ कल्ला, इंडोनेशिया के उप राष्ट्रपति और श्रीमती मेगावती सुकर्णोपुत्री, इंडोनेशिया की पूर्व राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग के आपसी हित के मामलों पर चर्चा की गई।	
दक्षिण अफ्रीका दौरा 19 मई 2015		डरबन में भारत ने दक्षिण संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक की 9वीं सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए।	
यूएस का दौरा 20-22 जून 2015		विदेश मंत्री ने योग समारोह के अंतरराष्ट्रीय दिवस के लिए न्यूयॉर्क का दौरा किया।	
नेपाल का दौरा, 25 जून 2015		नेपाल के पुनर्निर्माण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएनआर), भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए नेपाल सरकार द्वारा आयोजित एक दानदाता सम्मेलन में भाग लेने के लिए।	विदेश मंत्री ने भारत सरकार की ओर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता की घोषणा की जिनमें से एक चौथाई नेपाल के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए अनुदान के रूप में होगा।

थाईलैंड का दौरा 27-29 जून 2015		विदेश मंत्री ने भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग की 7 वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए और 27-29 जून 2015 बैंकॉक में 16वें विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक आधिकारिक दौरा किया था।	निम्नलिखित समझौतों / समझौता ज्ञापनों की हस्ताक्षर किए गए: 1. यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के लिए थाईलैंड-भारत संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक के सहमत कार्यवृत्त। 2. प्रत्यर्पण पर संधि के अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की मौखिक प्रक्रिया। 3. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन 4. आय पर करों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए थाईलैंड के राज्य सरकार बीच समझौता। 5. आयुर्वेद में "शैक्षणिक/ एकेडमिक चेयर" की स्थापना पर थाईलैंड, भारत गणराज्य की सरकार और रंगसित विश्वविद्यालय, आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।

मिस्र का दौरा 23-25 अगस्त 2015		विदेश मंत्री, श्री अब्दुल फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, श्री नाबिल अल अरबी, महासचिव, अरब राज्य लीग और श्री समेह हसन शौक्री, विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया, और द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों, कांसुलर मामलों और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।	यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए: (i) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और मिस्र के बीच समझौता ज्ञापन; (ii) भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद (एससीआईआर) और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर (एनआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन।
विदेश मंत्री का जर्मनी दौरा 26-28 अगस्त 2015		तीसरे भारत-जर्मनी अंतर्सरकारी परामर्श की तैयारी के लिए चांसलर मर्केल ने भारत की यात्रा की थी, जो अक्टूबर 2015 में भारत की गई। जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने जारी संयुक्त वक्तव्य में चुने गए आपसी हित के क्षेत्रों में चल रहे 2015 अप्रैल में प्रधानमंत्री की बर्लिन यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, निर्माण और कौशल विकास, नवाचार और शिक्षा, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में तीसरे आईजीसी के दौरान संभावित परिणामों पर चर्चा की।	
यूएस का दौरा 21-23 सितंबर 2015		विदेश मंत्री ने पहली मंत्रिस्तरीय भारत-अमेरिका सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता के लिए वाशिंगटन डीसी का दौरा किया। वाशिंगटन डीसी में आयोजित पहली मंत्रिस्तरीय भारत-अमेरिका सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता के बाद एक संयुक्त वक्तव्य 22 सितंबर, 2015 को जारी किया गया था। आतंकवाद पर एक संयुक्त घोषणा भी जारी किया गया था।	
यूएस का दौरा		विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों में भाग लेने के लिए न्यूयार्क का दौरा किया।	

29 सितंबर– 02 अक्तूबर 2015		उन्होंने 29 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में मौके पर आयोजित की पहली बार भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग भी लिया। पहली मंत्रिस्तरीय भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति 29 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में आयोजित जारी किया गया था।	
विदेश मंत्री का मालदीव, दौरा, 10-11 अक्तूबर, 2015		संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए। विदेश मंत्री ने यात्रा के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की और विदेश मंत्री, आर्थिक मामलों के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक भी आयोजित की। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संचार, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास, वाणिज्य दूत के मुद्दों और संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संबंध को आगे ले जाने पर सहमति हुई।	i) भारतीय एफएसआई और मालदीव एफओएसआईएम के बीच सहयोग। ii) खेल एवं युवा मामलों में सहयोग।
रूस का दौरा 19-21 अक्तूबर, 2015		विदेश मंत्री और रूस की सरकार के उपाध्यक्ष द्विपक्षीय मुद्दों पर और भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए उपायों पर व्यापक विचार विमर्श किया था। व्यापार और अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, पर्यटन और संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईटी क्षेत्र, निवेश के अवसरों, आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग, खनन, उर्वरक, नागरिक उड्डयन, बैंकिंग और वित्तीय मामलों और असैन्य परमाणु के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर मंत्रियों के बीच सहयोग पर सहमति। विदेश मंत्री ने रूसी संघ के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।	i. व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर-सरकारी आयोग की 21वीं सत्र की प्रोटोकॉल।

*****

अनुलग्नक 'ग'

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यात्राएं

विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा	**आयोजित वार्ताओं का ब्यौरा और आगे सहयोग के लिए क्षेत्रों का निर्णय**	**समझौतों पर हस्ताक्षर किए**	**टिप्पणियां**

(ख)			
पोलैंड के उप विदेश मंत्री 11-15 फरवरी 2014	नई दिल्ली में भारतीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और कोलकाता में एशियाई खनन कांग्रेस में भाग लेने के लिए।		
मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने 14 मई, 2014 को दौरा किया	भारत की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए		
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 26/27 मई, 2014 को भारत का दौरा किया	पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर 26/27 मई, 2014 के बीच भारत की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 26 मई, 2014 को भारत का दौरा किया। अगले दिन भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्षों के विदेश सचिव आगे द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे संपर्क करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सितंबर **2012** 'रोडमैप' के आधार पर व्यापार संबंधों की पूर्ण सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने हिंसा और आतंकवाद से संबंधित भारत की चिंताओं को रेखांकित किया। उन्होंने सीमाओं पर शांति और सौहार्द बनाए रखने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान नियंत्रण रेखा की पवित्रता को कायम रखने के महत्व को रेखांकित किया। आगे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में वर्तमान में चल मुंबई आतंकी हमले के मुकदमों में धीमी प्रगति के बारे में भारत की चिंता से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विकास और आपसी समृद्धि के लिए भागीदारी पर बनाए गए एक सार्क क्षेत्र में भारत की दूरदृष्टि को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साझा किया है और उम्मीद जताई कि भारत-पाकिस्तान के संबंधों में आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति अन्य सार्क पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में हाल के वर्षों में		

	प्रगति के समान तरीके से होगी।		
भूटान के प्रधानमंत्री ने 25-28 मई, 2014 को दौरा किया	प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए।		
नेपाल के प्रधानमंत्री ने 26-28 मई, 2014 को दौरा किया	प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए।		
ब्रिटेन के विदेश मंत्री जुलाई 2014	व्यापार और आर्थिक संबंधों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन-जन आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित इन यात्राओं के दौरान आयोजित द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया गया। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई।		
अमेरिका के राज्य सचिव 30 जुलाई-01 अगस्त 2014	संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव, जॉन केरी ने नई दिल्ली में 5वीं भारत-अमेरिका कार्यनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत का दौरा किया। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य की जारी किया गया था।		
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 4-5 सितंबर 2014	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए), रक्षा और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, असैन्य परमाणु करार, ज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और जल संसाधन पर चर्चाएँ आयोजित की गईं।	क. शांतिपूर्ण में सहयोग परमाणु ऊर्जा के उपयोग ख. खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन ग. जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीकरण घ. तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर) समझौता ज्ञापन (टीवीईटी)	
जर्मन विदेश मंत्री 8 सितंबर, 2014	उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और विदेश मंत्री के साथ उनकी बैठक में अफगानिस्तान, इराक, ईरान और यूक्रेन सहित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, नदियों की सफाई आदि सहित द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की।	तीसरी आईजीसी के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जर्मनी की चांसलर के बीच बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने बढ़ते खतरे और आतंकवाद और उग्रवाद की वैश्विक पहुंच के बारे में उनकी आम चिंता को साझा किया और इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए करीबी सहयोग बनाने के लिए अपनी तत्परता को दर्शाया। उन्होंने मध्य पूर्व में या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में, चाहे वह अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों	

		में आतंकवादी हिंसा की निंदा की। उन्होंने सफलतापूर्वक आतंकवाद से लड़ने और वहाँ हिंसा को समाप्त करने के लिए सीरिया में राजनीतिक समाधान का आह्वान किया। उन्होंने इराकी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने और एक समावेशी राज्य प्रणाली बनाने के प्रयासों के माध्यम से इराक में राष्ट्रीय सुलह और एकता के महत्व पर बल दिया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद निरोधक पर संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से आगे सहयोग को विकसित करने पर सहमत हुए। आतंकवाद का मुकाबला करने, जाली मुद्रा, नार्को और मानव तस्करी सहित सुरक्षा के क्षेत्र में दो सहमति पत्रों पर; और विमानन सुरक्षा भी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।	
चीनी राष्ट्रपति 17 से 19 सितंबर 2014	चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग 17 से 19 सितंबर 2014 के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर आए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात की और श्री नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों सहित कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार, रेलवे, अंतरिक्ष सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण, संस्कृति, औद्योगिक पार्क की स्थापना, जुड़वां-शहरों की व्यवस्था शामिल हैं। दोनों पक्षों ने नाथू ला के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक अतिरिक्त मार्ग खोलने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीनी पक्ष ने भारत में दो चीनी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए सहमति दी है और भारत में चीनी निवेश को बढ़ाने के लिए अपनी मंशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों, आर्थिक संबंधों और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों सहित द्विपक्षीय संबंधों में मुद्दों की पूरी रेंज पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सीमा पर बार-बार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि सीमा	1. भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चीन के जनवादी गणराज्य के के बीच तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रास्ते भारतीय तीर्थयात्रा (कैलाश मानसरोवर की यात्रा) के लिए एक नया मार्ग खोलने पर चीन की पीपुल्स गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन। 2. रेलवे में सहयोग को मजबूत बनाने पर भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। 3. रेलवे में सहयोग को मजबूत बनाने पर भारत गणराज्य सरकार के रेल मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के राष्ट्रीय रेल प्रशासन के बीच कार्य योजना। 4. भारत गणराज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के बीच पंचवर्षीय व्यापार और आर्थिक विकास योजना।	यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि "दोनों पक्ष 'शून्य सहिष्णुता' के साथ अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के प्रति अपनी दृढ़ विरोध को दोहराते हैं और कहा कि वे आतंकवाद का मुकाबला करने पर सहयोग करने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र के 1267, 1373, 1540 और 1624 प्रस्तावों को लागू करने की आवश्यकता पर भी बल

	क्षेत्र में शांति और सौहार्द आपसी विश्वास और आत्मविश्वास के लिए और हमारे रिश्ते की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए एक आवश्यक नींव बनती है। यह सुझाव दिया गया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस स्पष्टीकरण से शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रयासों में बहुत योगदान होगा। भारत और चीन के बीच जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार आदि कई बहुपक्षीय मुद्दों पर आम हित हैं। यह वैश्विक महत्व के अन्य मंचों जैसे ब्रिक्स, जी -20 और अन्य के अंदर दोनों पक्षों के बीच निकट सहयोग और समन्वय में परिलक्षित होता है। भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित बैठकें की जा रही हैं। दोनों पक्ष ने बातचीत और शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से और एक निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य ढंग से द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।	5. भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह की दसवीं सत्र के सहमत कार्यवृत्त 6. भारत गणराज्य के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के राज्य प्रशासन के बीच श्रव्य दृश्य सह-निर्माण पर समझौता। 7. भारत गणराज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता और सहयोग पर करार। 8. अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन। 9. सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने पर चीन जनवादी गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। 10. चीन जनवादी गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच के नेशनल बुक ट्रस्ट और प्रेस के राज्य प्रशासन, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म टेलीविजन सहयोग पर समझौता ज्ञापन। 11. चीन जनवादी गणराज्य के चीन खाद्य और औषधि प्रशासन और भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच औषधि प्रशासन और सहयोग पर की कार्य योजना। 12. मुंबई और शंघाई के बीच सिस्टर सिटी की स्थापना के संबंध पर समझौता 13. अहमदाबाद और गुआंगज़ौ के बीच सिस्टर सिटी के	दिया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के व्यापक मुद्दों पर काम करने के स्तर पर बढ़े द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया और आतंकवाद पर द्विपक्षीय परामर्श पहले से ही आयोजित किए गए और सार्थक पाए गए हैं।"

		संबंध स्थापित करने पर समझौता (गुजरात में हस्ताक्षर)। 14. गुजरात और गुआंग्डोंग बीच सिस्टर प्रांत / राज्य संबंध स्थापित करने पर समझौता 15. महाराष्ट्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना का समर्थन करने पर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और बीकी फोटॉन मोटर कं. लि. के बीच समझौता ज्ञापन। 16. गुजरात में औद्योगिक पार्क की स्थापना का समर्थन करने पर चीन विकास बैंक कारपोरेशन और इंडेक्सटीबी के बीच समझौता ज्ञापन (गुजरात में हस्ताक्षर)।	
कनाडा के विदेश मंत्री 13-14 अक्तूबर 2014	कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 14 अक्तूबर, 2014 को आयोजित दूसरी भारत कनाडा सामरिक वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत का दौरा किया। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।		
नेपाल के विदेश मंत्री 19-20 अक्तूबर 2014	काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण देने के लिए।		
वियतनाम के विदेश मंत्री 27-28 अक्तूबर, 2014	वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन तान दुंग ने 27-28, अक्तूबर, 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को कवर करते हुए राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। उच्च स्तरीय आदान प्रदान ने दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी को आगे गहरा, व्यापक और मजबूत किया है।	यात्रा के दौरान कुल **7** समझौतों / समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय सहित दूरसंचार विश्वविद्यालय, न्हा ट्रांग में अंग्रेजी भाषा और आईटी केंद्र की स्थापना; एएसआई द्वारा चाम स्मारकों की बहाली और संरक्षण; सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2015-17; ऑडियो विजुअल सहयोग; ओवीएल और पेट्रो वियतनाम के बीच समझौता; और ओएनजीसी और पेट्रो वियतनाम के बीच सहमति पत्र पर ।	

मेक्सिको के विदेश मंत्री अक्तूबर 2014	मेक्सिको के विदेश मंत्री, महामहिम जोस एंटोनियो मीडो कुरीब्रेना 22 अक्तूबर 2014 को भारत और मैक्सिको के बीच 6वें संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2014 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए।	शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष सहयोग पर इसरो और मैक्सिकन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच बैठक के मौके पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।	
उप प्रधानमंत्री और पोलैंड की अर्थव्यवस्था के मंत्री जनवरी 2015	वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग लेने के लिए और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए।		
अमेरिका के राज्य सचिव 11-12 जनवरी 2015	संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव, जॉन केरी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत का दौरा किया।		
मकदूनियाई प्रधानमंत्री 11-17 जनवरी 2015	उन्होंने गांधीनगर के वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में, जयपुर में सीआईआई-भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया और चेन्नई और कोलकाता में व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने वीजीएस मौके पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की और व्यापार सहयोग के मुद्दों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।		
सूरीनाम के विदेश मंत्री, 13 जनवरी, 2015	सूरीनाम के विदेश मंत्री, महामहिम विंस्टन लेकिन ने नई दिल्ली में 13 जनवरी 2015 को आयोजित 5 वें भारत-सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।		
जापान के विदेश मंत्री 16 से 18 जनवरी 2015.	विदेश मंत्री ने 17 जनवरी 2015 को जापान के विदेश मंत्री के साथ 8 वीं भारत-जापान सामरिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की। विदेश मंत्री किशिदा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री किशिदा ने भारत के साथ संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए जापान में नई सरकार के गठन के बाद यात्रा के लिए अपने पहले गंतव्य के रूप में भारत को चुना। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों		

	मंत्रियों ने सितंबर, 2014 में प्रधानमंत्री मंत्रियों की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। 'भारत-जापान निवेश संवर्धन भागीदारी' के तहत अगले पांच सालों में भारत में जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना करने की परिकल्पना की गई। अक्तूबर 2014 तक 137 की वृद्धि के साथ भारत में जापानी कंपनियों की संख्या 1209 तक पहुंच गई। जापान ने जापान प्लस जैसी नई पहल के शुभारंभ सहित भारत में कारोबारी माहौल में सुधार की सराहना की। भारत और जापान 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-जापान समझौते के समापन की 30 वीं वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।		
श्रीलंका के विदेश मंत्री, 17-19 जनवरी, 2015	श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा के लिए तैयारी		
अमेरिका के राष्ट्रपति 25-27 जनवरी 2015	अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के 66 वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 25-27 जनवरी, 2015 के बीच भारत का दौरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान तीन दस्तावेज संयुक्त रूप से जारी किए गए थे। इनमें यात्रा से परिणामों की रूपरेखा तैयार करने और द्विपक्षीय सहयोग पर आगे का मार्ग बताया गया है। ये हैं: "सांझा प्रयास, सबका विकास" शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य; सभी की समृद्धि के लिए साझा प्रयास; लम्बे समय से भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार की ओर मित्रता के लिए भारत-अमेरिका दिल्ली घोषणा;		

	एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत-अमेरिका संयुक्त सामरिक दृष्टि क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए।		
फ्रांसीसी विदेश कार्य और अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री 05 फरवरी, 2015	दिल्ली सतत शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विदेश मंत्री, रेल मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की।		
सिंगापुर के राष्ट्रपति 08-11 फरवरी, 2015	भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत के माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने भारत और विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की वृद्धि पर विचार-विमर्श और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को मजबूत किया था। चर्चाओं में स्मार्ट शहरों, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और आतंकवाद से निपटने आदि जैसे क्षेत्रों को कवर किया।		
मालदीव के विदेश मंत्री, 14-15 फरवरी, 2015	मालदीव के घटनाक्रम पर विदेश मंत्री ने जानकारी देने के लिए।		
श्रीलंका के राष्ट्रपति, 15-18 फरवरी, 2015	चर्चाओं में श्रीलंका के राजनीतिक घटनाक्रम सहित आपसी हित के मुद्दों की एक विस्तृत रेंज को कवर किया गया।	i) शांतिपूर्ण में सहयोग पर श्रीलंका और भारत के बीच समझौते के तहत परमाणु ऊर्जा का उपयोग। ii) वर्ष 2015-18 के लिए श्रीलंका और भारत के बीच सांस्कृतिक सहयोग के कार्यक्रम। iii) नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन। iv) कार्य-योजना 2015-2016के तहत कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	
बहरीन के विदेश मंत्री 22-23 फरवरी, 2015	द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर चर्चा की गई थी।	जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन	

लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री 1-2 मार्च, 2015	उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत सरकार की नई योजनाओं यथा द्विपक्षीय व्यापार, बैंकिंग, निवेश के अवसरों सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की जैसे स्मार्ट सिटी, स्वच्छ गंगा, कौशल विकास और मेक इन इंडिया।	विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के मुद्दे पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसे लक्ज़मबर्ग पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया था।	
ब्रिटेन के विदेश मंत्री मार्च 2015	इन यात्राओं के दौरान आयोजित द्विपक्षीय विचार-विमर्श में व्यापार और आर्थिक संबंधों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई।		
थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 10-11 मार्च 2015	यह 10-11 मार्च 2015 को भारत की सरकारी यात्रा थी और गणमान्य अतिथि ने सातवें दिल्ली संवाद में भाग लिया		
कतर के अमीर 24-25 मार्च 2015	द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर चर्चा की गई थी।	सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण पर करार; विदेश सेवा संस्थान और कतर राजनयिक संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन; सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन तथा आपसी सहयोग और समाचार के आदान-प्रदान के लिए करार	
स्पेन के विदेश मंत्री अप्रैल 2015	विदेश मंत्री और स्पेनिश विदेश मंत्री के बीच आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श के आयोजित की गई। एक संयुक्त विज्ञप्ति में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा, रक्षा सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला, सुरक्षा, आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श के परिणामों को दर्शाते हुए जारी किया गया था।	इस यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों के बीच चर्चा क्षेत्रों में से एक आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। दोनों मंत्रियों ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए और आतंकवादी हमलों की जोरदार निंदा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हिंसक उग्रवाद के प्रसार के	

		बारे में चिंता जताते हुए मंत्रियों ने एक व्यापक सुरक्षा-सह-विकास के दृष्टिकोण के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के लिए पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता को दोहराया जो भारत और स्पेन दोनों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। दोनों मंत्रियों ने आम सामरिक सुरक्षा चुनौतियों, विचारों के विनिमय का आकलन करने और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के नेतृत्व में एक नियमित रूप से सुरक्षा नीति वार्ता का शुभारंभ किया। उद्घाटन सुरक्षा नीति वार्ता का आयोजन मैड्रिड में 22 सितंबर को किया गया था।	
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 12-15 अप्रैल, 2015	विदेश मंत्रियों की वार्षिक रूपरेखा वार्ता (एफएमएफडी) में भाग लेने के लिए। विदेश मंत्री के साथ एफएमएफडी के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं सामरिक भागीदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, असैन्य परमाणु सहयोग, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, लोगों को जोड़ने, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों को लोगों सहित चर्चा की गई। यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।		
बेलारूस के विदेश मंत्री 14-16 अप्रैल, 2015	विदेश मंत्री और बेलारूस के विदेश मंत्री ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संलग्नता, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, संस्कृति के साथ-साथ बेलारूस के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति के साथ जून 2015 में बेलारूस राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की।		
अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति 27-29 अप्रैल 2015	राष्ट्रपति गनी और प्रधानमंत्री ने व्यापक चर्चा और द्विपक्षीय सहयोग की गतिविधियों का आयोजन किया और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा		

	वातावरण समीक्षा की। दोनों नेताओं ने भागीदारी परिषद और इससे संबंधित संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की व्यवस्था के माध्यम से कार्यनीतिक साझेदारी के उद्देश्यों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को अफगानिस्तान में जारी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के महत्वपूर्ण बदलाव के लिए भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि वे इस पर सहमत हैं कि उनके क्षेत्रों को किसी भी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।		
ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री 11-15 मई, 2015	विदेश मंत्री और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, आतंकवाद का मुकाबला, वाणिज्य दूत, क्षमता निर्माण और संस्कृति जैसे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा की थी।	2015-17 की अवधि के लिए भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग पर प्रोटोकॉल।	
हंगरी के विदेश और व्यापार मंत्री 20 मई 2015	उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और व्यापार जगत के नेताओं से मुलाकात की।		
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री 5-6 जून 2015	उनके साथ एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आया। दोनों पक्षों ने व्यापक आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। डच दक्षताओं और भारत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मौजूदा जरूरतों के बीच गहरी समानताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सहमति व्यक्त की कि नीदरलैंड को जल प्रबंधन, साफ पानी की प्रौद्योगिकियों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग, बुनियादी ढांचे के विकास, बंदरगाह और हवाई अड्डे के उन्नयन, स्मार्ट सिटी, अक्षय ऊर्जा और बिजली, साफ-सफाई और ठोस	नेताओं ने दोनों देशों के लिए हिंसक उग्रवाद और आतंकवाद के प्रसार से उत्पन्न गंभीर खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति और जल्दी के कार्यान्वयन सहित एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय	

	अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण और डेयरी फार्मिंग, बागवानी और फूलों की खेती के प्रमुख क्षेत्रों में एक पसंदीदा भागीदार बनने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर रखा गया था। भारी उद्योग विभाग, भारत और आर्थिक कार्य मंत्रालय के बीच सहयोग के एक संयुक्त कार्यक्रम पर नीदरलैंड में यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्ष सहयोग के लिए एक रोडमैप के माध्यम से आपसी हित के अनेक विशिष्ट प्रयासों के लिए पर सहमत हुए।	समुदाय द्वारा एक एकीकृत और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के समापन की बात को दोहराया । दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में 19 जून 2015 को पहली बैठक बुलाई थी जिसमें आतंकवाद के साथ मुकाबले पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का स्वागत किया गया। संयुक्त कार्य समूह ने आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने पर संयुक्त क्षमता निर्माण के साथ ही चर्चा की बहुपक्षीय सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग का आह्वान किया।	
तंजानिया के राष्ट्रपति, 17-20 जून 2015	राज्य दौरा	i) सरकारी आंकड़ों में एक सहयोगी कार्यक्रम की स्थापना पर तंजानिया में पूर्वी अफ्रीका सांख्यिकीय प्रशिक्षण केंद्र (ईए एसटीसी) और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एन एस एसटीए) के बीच समझौता ज्ञापन ii) ईएएस टीसी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बीच समझौता ज्ञापन - भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई) iii) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन iv) तंजानिया और भारत के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	
तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री 21 जुलाई, 2015	श्री बेमिराट होजामुहम्मदोव ने श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया। दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और दोनों पक्षों के बीच हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए सहमति हुए। उन्होंने तापी परियोजना के प्रति अपनी		

	प्रतिबद्धताओं को दोहराया और इस परियोजना को जल्दी प्रारंभ करने की दिशा में काम करने का वादा किया।		
लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अगस्त 2015	दोनों देशों के बीच 8 वें संयुक्त आयोग की बैठक के संबंध में। संयुक्त आयोग की बैठक में भारत और लाओ पीडीआर के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की।		
मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, 6-7 अगस्त 2015	राजकीय यात्रा	नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	
ईरान के विदेश मंत्री 14 अगस्त 2015	विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श किए। उन्होंने जहाजरानी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से भी मुलाकात की।		
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 19 अगस्त, 2015	राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी श्रीमती सुवरा मुखर्जी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए।		
मार्शल द्वीप, नौरू, पलाऊ के राष्ट्रपति; फिजी, नियू, पीएनजी, समोआ, तुवालु, वानुअतु के प्रधानमंत्रिगण; माइक्रोनेशिया के उप राष्ट्रपति और कूका द्वीप समूह, किरिबाती, सोलोमन द्वीप, टोंगा के वरिष्ठ मंत्रिगण और अधिकारी। 21 अगस्त 2015	भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग के लिए फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन (एफआईपीआईसी) में भाग लेने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री और फिजी, पापुआ न्यू गिनी और वानुअतु के प्रधानमंत्रियों के बीच पर 21 अगस्त 2015 को जयपुर में शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय चर्चाएं की गई। इसमें विचार विमर्श के अलावा आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर केंद्रित जैसे रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्र, नारियल, जूट क्षेत्रों आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर वार्ता आयोजित की गई।	शिखर सम्मेलन के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, हालांकि, प्रधानमंत्री ने प्रशांत द्वीप देशों को सहायता के लिए सहयोग बढ़ाया, जैसे 14 पीआईसी में से प्रत्येक में आईटी लैब्स की स्थापना, 14 पीआईसी **में** 2800 घरों का सौर विद्युतीकरण, पीआईसी के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-टूरिस्ट वीजा अनुदान, शिक्षा के क्षेत्र, संस्कृति, जलवायु और रक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण ।	
सेशेल्स के राष्ट्रपति 25-27 अगस्त	राजकीय यात्रा	i) ब्लू अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग और ब्लू अर्थव्यवस्था पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए फ्रेमवर्क पर 22 प्रोटोकॉल। ii) संशोधित द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते की अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन iii) कृषि अनुसंधान के लिए सेशेल्स कृषि एजेंसी और	

		भारतीय परिषद के बीच कृषि समझौता ज्ञापन iv) कर सूचना विनिमय समझौता v) एक "डोर्नियर-228 समुद्री विमान के प्रदान करने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच समझौता ज्ञापन	
संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री 03-04 सितंबर 2015	द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर चर्चा की गई थी।	पर्यटन; उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान; विनिर्देशों और मैट्रोलोजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; दूरसंचार नियामक प्राधिकरणों और फिक्की और उसके संयुक्त अरब अमीरात सहयोगी के बीच के बीच सहयोग।	
श्रीलंका के प्रधानमंत्री की यात्रा, 14-16 सितम्बर, 2015	दौरे के दौरान चर्चाओं में श्रीलंका में राजनीतिक घटनाक्रम सहित आपसी हित के मुद्दों की एक विस्तृत रेंज को कवर किया	i) सार्क क्षेत्र के लिए उपग्रह की कक्षा आवृत्ति समन्वय पर भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समझौते। ii) स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, चैरिटेबल ट्रस्ट और शिक्षा और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं (एसडीपी) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता ज्ञापन का नवीकरण। iii) श्रीलंका में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की स्थापना पर पत्र का आदान-प्रदान	
जर्मन चांसलर की यात्रा 4 – 6 अक्तूबर, 2015	तीसरे भारत-जर्मनी अंतर्सरकारी परामर्श के लिए। उनके साथ जर्मन विदेश मंत्री डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टीन्मीयर, 3 संसदीय राज्य सचिव और 2 राज्य सचिवों सहित 4 कैबिनेट मंत्रिगण आए थे। प्रधानमंत्री और चांसलर मार्केल ने द्विपक्षीय आर्थिक एजेंडा, रक्षा सहयोग, खुफिया आदान-प्रदान, निर्यात नियंत्रण, आतंकवाद और आपसी चिंताओं के अन्य क्षेत्रों सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की। नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर, सीरिया, यूक्रेन, अफगान-पाक, चीन, की	तीसरे आईजीसी के दौरान सुरक्षा, व्यापार और निवेश, उत्पादन, कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा, रेलवे, नवाचार और शिक्षा, पर्यावरण, भाषा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित 18 समझौतों को अंतिम रूप दिया और हस्ताक्षर किए गए थे : **(I)** भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत में एक विदेशी भाषा और जर्मनी में आधुनिक भारतीय भाषा के	

	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यता के लिए के लिए जी-4 की पहल, यूरोप में शरणार्थी संकट आदि पर गहराई से विचारों का आदान-प्रदान किया। अप्रैल 2015 के दौरान प्रधानमंत्री की बर्लिन यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों की पहचान करने में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए।	संवर्धन के रूप में जर्मन के संवर्धन के बारे में जर्मनी के संघीय गणराज्य के संघीय विदेश कार्यालय के बीच आशय का संयुक्त घोषणा ; **(Ii)** भारत सरकार और जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच विकास सहयोग पर बातचीत का सारांश रिकार्ड; (iii) भारत-जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारी के संबंध में भारत-जर्मन विकास सहयोग पर भारत गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास जर्मनी के संघीय गणराज्य और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (iv) एक ओर भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और दूसरी ओर जर्मनी गणराज्य के शिक्षा और अनुसंधान के संघीय मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य आर्थिक सहयोग और विकास के संघीय मंत्रालय के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर समझौता संयुक्त ज्ञापन (v) भारत गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य के आंतरिक मंत्रालय के बीच संघीय सुरक्षा सहयोग पर (vi) भारत गणराज्य के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य की आंतरिक उड्डयन सुरक्षा बीच समझौता ज्ञापन (vii) भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और सहयोग पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के आंतरिक मंत्रालय की संघीय में मंत्रालय के बीच आशय की संयुक्त घोषणा के आंतरिक मंत्रालय की संघीय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र;; (viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (भारत गणराज्य की सरकार) मंत्रालय के बीच संयुक्त घोषणा और शिक्षा के संघीय मंत्रालय और इंडो-जर्मन विज्ञान के कार्यकाल के विस्तार पर अनुसंधान (जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार)	

		और प्रौद्योगिकी केंद्र (आईजी एसटीसी); (ix) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बीच समझौता ज्ञापन, उच्च शिक्षा में इंडो-जर्मन भागीदारी पर भारत और जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डी एएडी), जर्मनी (आईजीपी); (x) कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण, (एमओए और परिवार कल्याण), भारत सरकार, और पौध संरक्षण उत्पादों पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा (बीवीएल) के संघीय कार्यालय के बीच आशय का संयुक्त घोषणा; (xi) परिवहन और जर्मनी के संघीय गणराज्य और भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय के डिजिटल बुनियादी सुविधाओं के संघीय मंत्रालय के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के आगे विकास पर आशय की संयुक्त घोषणा; (xii) भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम, भारत सरकार, और फ्रॉनहॉफर सोसायटी विभाग के बीच जर्मनी विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन,; (xiii) भारत में जर्मन कंपनियों के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने पर संयुक्त घोषणा; (xiv) जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार और कंपनियों के अधिकारियों और भारत से कनिष्ठ अधिकारी के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने पर भारत गणराज्य की सरकार के बीच संयुक्त घोषणा; (xv) जोखिम मूल्यांकन के लिए संघीय संस्थान (बीएफआर) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के बीच खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर आशय का संयुक्त वक्तव्य; (xvi) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर खाद्य सुरक्षा (बीवीएल) के	

		संघीय कार्यालय के बीच आशय का संयुक्त वक्तव्य; (xvii) कृषि अध्ययन में सहयोग पर भारत (एएससीआई) की जर्मन एग्रीबिजनेस एलायंस और कृषि कौशल परिषद के बीच समझौता ज्ञापन; (xviii) प्राकृतिक विज्ञान में भारतीय युवा वैज्ञानिक के लिए लिंडाउ नोबेल पुरस्कार विजेता बैठक में भागीदारी पर समर्थन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत गणराज्य की सरकार (डीएसटी), और लिंडाउ नोबेल पुरस्कार विजेता बैठक के लिए परिषद (परिषद), और फाउंडेशन (फाउंडेशन) के विभाग के बीच लिंडाउ नोबेल पुरस्कार विजेता बैठक आशय पत्र के लिए।	
पोलैंड के उप विदेश मंत्री 5-6 अक्तूबर 2015	भारत-मध्य यूरोप व्यापार मंच में भाग लेने के लिए। पोलैंड मंच में एक भागीदार देश था।	बैठक के दौरान राजनयिक पासपोर्ट धारक के लिए एक समझौता ज्ञापन पर वीजा पर अधित्यजन समझौते हस्ताक्षर किए गए थे।	
उरुग्वे के विदेश मंत्री 8 अक्तूबर 2015	उरुग्वे के विदेश मामलों के मंत्री एच.ई. रोडोल्फो निन नोवो 8 अक्तूबर 2015 को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री के साथ चर्चा आयोजित की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की और व्यापार और निवेश, संस्कृति, पर्यटन और कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई।		
सिंगापुर के विदेश मंत्री 12 अक्तूबर 2015	भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने के लिए भारत का दौरा किया, जिसके दौरान संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।		
फिलीपींस के विदेश मंत्री 13-15 अक्तूबर, 2015	श्री अल्बर्ट डेल रोसारियो एफ, सचिव (विदेश मंत्री), विदेश विभाग, फिलीपींस गणराज्य ने 13-15 अक्तूबर 2015 के बीच भारत का दौरा किया के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर तीसरे संयुक्त आयोग की	प्रत्यर्पण संधि का अनुसमर्थन के साधन का आदान-प्रदान किया गया था, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान	

	सह-अध्यक्षता की। उन्होंने इस यात्रा के दौरान उप राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।	2016-18 पर कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए	
नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 17-19 अक्तूबर, 2015	पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर उनकी पहली विदेश यात्रा।		
ब्राजील के विदेश मंत्री, 18-19 अक्तूबर, 2015	ब्राजील के विदेश मंत्री एच.ई. श्री मौरो विएरा ने 18-19 अक्तूबर 2015 को भारत का दौरा किया। भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की 7 वीं बैठक (जेसीएम) माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और ब्राजील के विदेश संबंध मंत्री की सह-अध्यक्षता में 19 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। इसमें कृषि, ऊर्जा और खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई । इसमें क्षेत्रीय द्विपक्षीय सहयोग, और बहुपक्षीय मुद्दों का जायजा लेने के लिए "विदेश कार्यालय परामर्श" आयोजित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने पर सहमति हुई।		
भूटान के विदेश मंत्री 22-28 अक्तूबर, 2015	उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा। उन्होंने इंदौर में तीसरे अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन में भी भाग लिया।		
जिबूती के राष्ट्रपति और जिबूती के विदेश मंत्री 23-29 अक्तूबर, 2015	उन्होंने अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों की बैठक में और तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की।		
मिस्र के राष्ट्रपति, 23-29 अक्तूबर, 2015	उन्होंने अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों की बैठक और तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया।		

	राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और आतंकवाद के साथ-साथ बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।		
मोरक्को के राजा मोहम्मद षष्ठम और मोरक्को के विदेश मंत्री 23-29 अक्तूबर 2015	उन्होंने अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों की बैठक और तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राजा ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। उन्होंने फॉस्फेट के आयात, फॉस्फोरिक एसिड और उर्वरक के उत्पादन में संयुक्त उद्यम और भारतीय वस्त्रों के निर्यात, ऑटोमोबाइल घटकों, आईटी उत्पादों और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की।		
सोमालिया के राष्ट्रपति और सोमालिया के विदेश मंत्री 23-29 अक्तूबर 2015	उन्होंने अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों की बैठक और तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। उन्होंने पायरेसी, समुद्री सुरक्षा, कृषि, मत्स्य, बुनियादी सुविधाओं, सोमाली राजनयिकों प्रशिक्षण मुद्दों पर चर्चा की।		
दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति और दक्षिण सूडान के विदेश मंत्री 23-29 अक्तूबर 2015	उन्होंने अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों की बैठक और तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। उन्होंने ऊर्जा, कृषि, मूलसंरचना, मानव संसाधन विकास, दक्षिण सूडान शांति प्रक्रिया के मुद्दों पर चर्चा की।		
सूडान के राष्ट्रपति और सूडान के विदेश मंत्री 23-29 **अक्तूबर** 2015	उन्होंने अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों की बैठक और तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। उन्होंने विकास भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की।		
ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री 23-29 अक्तूबर 2015	उन्होंने अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों की बैठक और तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के		

	साथ मुलाकात की। व्यापार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और वैज्ञानिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।		
उप राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, अंगोला 26-30 अक्टूबर, 2015	विचार-विमर्श द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को कवर किया गया।		तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, साओ टोम और प्रिंसिपे 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, इक्वेटोरियल गिनी 26-30 अक्तूबर 2015			
नाइजीरिया के राष्ट्रपति 26-30 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री, कैमरून 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, बेनिन 26-30 अक्तूबर 2015			
चाड के राष्ट्रपति 26-30 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री, डीआरसी 26-30 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री, आरओसी 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, गैबॉन 26-30 अक्तूबर 2015			

राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, घाना 26-30 अक्तूबर 2015	आईएएफएस-तृतीय के मौके पर आयोजित दौरा करने के साथ बैठकों के दौरान, सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा आपसी चिंताओं के वैश्विक मुद्दों, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुधार आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार संगठन वार्ता में सहयोग के लिए चर्चा की गई। कुछ बैठकों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग पर भी चर्चा की गई।		
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, सिएरा लियोन 26-30 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री, बुर्किना फासो 26-30 अक्तूबर 2015			
लाइबेरिया के राष्ट्रपति 26-30 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री टोगो 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, गिनी 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, माली 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, नाइजर 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, मॉरिटानिया 26-30 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, सेनेगल 26-30 अक्तूबर 2015			
उप-राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, गाम्बिया 26-30 अक्तूबर 2015			
प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री,			

केप वर्डे 26-30 अक्तूबर 2015			
गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति 26-30 अक्तूबर, 2015			
जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति 26-29 अक्तूबर 2015			तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
स्वाजीलैंड के महामहिम राजा, 26-29 अक्तूबर 2015			
दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य के राष्ट्रपति 26-29 अक्तूबर 2015			
युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति 26-29 अक्तूबर 2015			
राष्ट्रपति, कोमोरोस संघ 26-29 अक्तूबर 2015			
केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति 26-29 अक्तूबर 2015			
मेडागास्कर गणराज्य के राष्ट्रपति 26-29 अक्तूबर 2015			
नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति, 26-29 अक्तूबर 2015			
उप राष्ट्रपति, बोत्सवाना गणराज्य 26-29 अक्तूबर 2015			
उप राष्ट्रपति, तंजानिया 26-29 अक्तूबर 2015			
उप राष्ट्रपति, बुरुंडी गणराज्य			

26-29 अक्तूबर 2015			
उप राष्ट्रपति, जाम्बिया के गणराज्य 26-29 अक्तूबर 2015			
प्रधानमंत्री, इथियोपिया 26-29 अक्तूबर 2015			
प्रधानमंत्री, लेसोथो के किंगडम 26-29 अक्तूबर 2015			
प्रधानमंत्री, मॉरीशस			
प्रधानमंत्री, मोजाम्बिक 26-29 अक्तूबर 2015			
प्रधानमंत्री, रवांडा 26-29 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री, इरिट्रिया 26-29 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री, मलावी 26-29 अक्तूबर 2015			
विदेश मंत्री सेशेल्स 26-29 अक्तूबर 2015			
मॉरीशस के प्रधानमंत्री, 28 अक्तूबर से 1 नवंबर 2015	भारत अफ्रीका के विदेश शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए		
भूटान के प्रधानमंत्री 13-17 नवम्बर 2015	गोवा में दूसरे भारत विचार कॉन्क्लेव 2015 में भाग लेने के लिए।		
फ्रांसीसी विदेश और अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री 20 नवंबर 2015	29 नवम्बर - 11 दिसम्बर 2015 से पेरिस में आयोजित सीओपी 21 के लिए तैयारी करने के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण राज्य वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने श्री सुरेश प्रभु, रेल मंत्री और कोयला, वियुत, नवीन और		

	नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, श्री पीयूष गोयल, (स्वतंत्र प्रभार) के साथ आयोजित बैठकों में भी हिस्सा लिया। ये विचार-विमर्श मुख्य रूप से सीओपी 21, ऊर्जा दक्षता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्तपोषण आदि पर केंद्रित थे।		
मालदीव के विदेश मंत्री, 21-22 नवम्बर, 2015	मालदीव के घटनाक्रम पर विदेश मंत्री को जानकारी देना।		

*****